

अध्याय 1

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दो वर्षों में देखी गई सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 5 प्रतिशत से कम की वृद्धि दर पर वर्ष 2014-15 में विजय हासिल करने के लिए तैयार बैठी है। पिछले दो वर्षों में विकास में आई मंदी व्यापक आधार वाली थी जिसने विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित किया। इस अवधि में मुद्रास्फीति में भी कमी आई, लेकिन फिर भी वह संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंची जिसकी वजह खाद्य मुद्रास्फीति का अधिक होना था। फिर भी, बृहत् आर्थिक स्थिरीकरण के मोर्चे पर हुआ घटनाक्रम, विशेषकर बाह्य आर्थिक स्थिति में हुआ जबरदस्त सुधार, जब चालू खाता घाटा (कैड) दो वर्षों के बेहद चिन्तनीय स्तर के बाद गिरकर 2013-14 में नियंत्रणीय स्तर पर आ पहुंचा, एक सकारात्मक विशेषता थी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केन्द्र के राजकोषीय घाटे में भी घोषित किए गए मध्यावधि नीतिगत दृष्टिकोण के अनुरूप लगातार दो वर्ष तक कमी हुई। यही स्थिति और बेहतर कल की उम्मीद को दर्शाते हुए वित्तीय बाजारों में उछाल आया है। मुद्रास्फीति कम होने से मौद्रिक नीति के रुख में नरमी आएगी और निवेशकों का आत्मविश्वास जागेगा तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में साधारण सुधार होने की संभावना के चलते, जो विशेषकर कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में हुए बेहतर निष्पादन के कारण होगा, हमारी अर्थव्यवस्था 2014-15 और उससे आगे भी बेहतर विकास संभावनाओं की उम्मीद कर सकती है।

1.2 2005-06 और 2007-08 के बीच लगातार तीन वर्षों तक 9 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व विकास दर प्राप्त करने और 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट से तेजी से उबरने के पश्चात्, आज भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है जिसकी परिणति लगातार दो वर्षों तक अर्थात् 2012-13 और 2013-14 में स्थिर कीमतों पर उपादान लागत पर स.घ.उ. की विकास दर के 5 प्रतिशत से नीचे पहुंचने के रूप में हुई। पूर्व में लगातार दो वर्षों तक 5 प्रतिशत से कम की स.घ.उ. विकास दर, अंतिम बार 25 वर्ष पहले 1986-87 और 1987-88 में देखी गई थी।

घरेलू संरचनागत और बाहरी कारकों के कारण आर्थिक विकास में मंदी आई है। 25 वर्षों में पहली बार 5 प्रतिशत से कम की विकास दर लगातार दो वर्षों तक देखी गई।



चित्र 1.1 : वास्तविक स.घ.उ. में वृद्धि (प्रतिशत)

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

सारणी 0.1 : मुख्य संकेतक

आंकड़ा श्रेणियां	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1. स.घ.उ. और संबंधित संकेतक						
स.घ.उ. (वर्तमान बाजार मूल्य)	₹ करोड़	6477827	7784115	9009722 ² सं.	10113281 ¹ सं.	11355073अ.अ.
वृद्धि दर	%	15.1	20.2	15.7	12.2	12.3
स.घ.उ. (घटक लागत 2004-05 के मूल्य पर)	₹ करोड़	4516071	4918533	5247530 ² सं.	5482111 ¹ सं.	5741791अ.अ.
वृद्धि दर	%	8.6	8.9	6.7	4.5	4.7
बचत दर	स.घ.उ. का %	33.7	33.7	31.3	30.1	अनु.
पूंजी निर्माण (दर)	स.घ.उ. का %	36.5	36.5	35.5	34.8	अनु.
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (मौजूदा कीमतों पर उपादान लागत)	₹	46249	54021	61855	67839	74380
2. उत्पादन						
खाद्यान्न	मिलियन टन	218.1	244.5	259.3	257.1	264.4क
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ^ख (वृद्धि)	%	5.3	8.2	2.9	1.1	-0.1
विद्युत उत्पादन (वृद्धि)	%	6.1	5.5	8.2	4.0	6.1
3. कीमतें						
मुद्रास्फीति (थो.मू.सू.) (औसत)	%	3.8	9.6	8.9	7.4	6.0
मुद्रास्फीति सीपीआई (आई डब्ल्यू) (औसत)	%	12.4	10.4	8.4	10.4	9.7
4. वैदेशिक क्षेत्र						
निर्यात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% प्रतिशत	-3.5	40.5	21.8	-1.8	4.1
आयात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% प्रतिशत	-5.0	28.2	32.3	0.3	-8.3
चालू खाता घाटा (सीएडी)/स.घ.उ.	%	-2.8	-2.8	-4.2	-4.7	-1.7
विदेशी मुद्रा भण्डार ^ग	बिलियन अमरीकी डालर	279.1	304.8	294.4	292.0	304.2
औसत विनिमय दर ^घ	₹/अमरीकी डालर	47.44	45.56	47.92	54.41	60.5
5. मुद्रा तथा ऋण						
स्थूल मुद्रा (एम 3) (वार्षिक)	% परिवर्तन	16.9	16.1	13.2	13.6	13.3
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण	% परिवर्तन	16.9	21.5	17	14.1	13.9
6. राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)						
सकल राजकोषीय घाटा	स.घ.उ. का %	6.5	4.8	5.7	4.9	4.5ड
राजस्व घाटा	स.घ.उ. का %	5.2	3.2	4.4	3.6	3.2ड
प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. का %	3.2	1.8	2.7	1.8	1.2ड
7. जनसंख्या						
	मिलियन	अनु.	1210च	अनु.	अनु.	अनु.

प्र.सं.अ. 1 संशोधित अनुमान; द्वि.सं.अ. 2 संशोधित अनुमान अ.अ. अनंतिम अनुमान

उ.न. उपलब्ध नहीं

क तृतीय अग्रिम अनुमान

ख औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष (2004-05 = 100) पर 2005-06 से संशोधित किए गए हैं।

ग मार्चति

घ औसत विनिमय दर (आरबीआई संदर्भ दर)

ड 2013-14 के लिए राजकोषीय संकेतक वास्तविक अनंतिम आंकड़ों पर आधारित है।

च जनगणना 2011

(चित्र 1.1)। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामान्य गिरावट और यूरो क्षेत्र में व्याप्त संकटों से उत्पन्न वैश्विक संभावनाओं में बनी निरंतर अनिश्चितता के साथ-साथ घरेलू संरचनागत रुकावटों और स्फीतिकारी दबावों के कारण, मंदी की स्थिति लंबे समय तक रही। यह गिरावट मौटे तौर पर, अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त प्रवृत्तियों के अनुरूप है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक गहन है। भारत की विकास दर 2004-05 से 2011-12 के दौरान के 8.3 प्रतिशत वार्षिक की औसत से गिरकर 2012-13 और 2013-14 में 4.6 प्रतिशत की औसत पर पहुंच गई। इस अवधि में (कैलेण्डर-वर्ष आधार पर) चीन सहित उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में औसत विकास दर 6.8 प्रतिशत से गिरकर 4.9 प्रतिशत रह गई। जो बात मुख्यतः चिंताजनक है, वह है-विनिर्माण विकास में गिरावट जो 2012-13 और 2013-14 में औसतन 0.2 प्रतिशत वार्षिक है।

1.3 मुद्रास्फीति विकास दर में गिरावट के अतिरिक्त, लगातार अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करती रही। यद्यपि औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति 2011-12 के 8.9 प्रतिशत और 2012-13 के 7.4 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 2013-14 में 6.0 प्रतिशत तक हो गई, फिर भी यह संतोषजनक स्तर पर नहीं है। इसके अलावा, खाद्य वस्तुओं में डब्ल्यूपीआई जो 2013-14 को समाप्त हो रहे पांच वर्षों में औसतन 12.2 प्रतिशत वार्षिक रही, खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। सौभाग्यवश, मुद्रास्फीति का वृद्धिकारी रुख जिसने विकास, बचतों, निवेश और खपत की गिरावट में भूमिका अदा की, अब धीमा हो गया प्रतीत हो रहा है।

1.4 वैदेशिक क्षेत्र में 2013-14 की पहली तिमाही के बाद उल्लेखनीय सुधार देखा गया और 2012-13 के 4.7 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष की समाप्ति पर चालू खाता घाटा (सीएडी) स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत रहा। 28 अगस्त 2013 को रुपया एक अमरीकी डालर के मुकाबले तेजी से गिरकर 68.36 रुपये हो जाने के पश्चात्, जिसका कारण संयुक्त राज्य अमरीका में नकदी की मात्रात्मक सुलभता में संभावित कमी लाना था, रुपया धीरे-धीरे मजबूत हुआ और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गये उपायों के चलते, मार्च 2014 में वर्षान्त पर औसत विनिमय पर प्रति अमरीकी डालर 61 रुपये थी। विदेशी मुद्रा भंडार सितम्बर 2013 के आरंभ में 275 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से लगभग 40 बिलियन अमरीकी डालर बढ़कर 20 जून, 2014 को 314.9 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। विदेशी मोर्चे पर हुए इन घटनाक्रमों से कुछ आशा जागृत हुई कि भारतीय अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका में नकदी की मात्रात्मक सुलभता सहित वैश्विक नीति की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बेहतर रूप से तैयार है राजकोषीय पक्ष पर भी सुधार देखा गया है, जहां राजकोषीय घाटा 2011-12 के स.घ.उ. के 5.7 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 4.9 प्रतिशत और 2013-14 में 4.5 प्रतिशत हो गया। यह सुधार ज्यादातर वृद्धित राजस्व के बजाए व्यय में कटौती करके आया। फिर भी, राजकोषीय और चालू खाता घाटों में हुए सुधार बृहत आर्थिक स्थिरीकरण के लिए शुभ लक्षण हैं।

1.5 दोनों घाटों के मोर्चे पर हुआ सुधार निश्चित रूप से 2014-15 में उच्च विकास पर असर डालेगा, लेकिन इस सुधार की रफ्तार धीमी रह सकती है। 2012-13 की अंतिम दो तिमाहियों (ति 3 और ति 4) के दौरान 4.4 प्रतिशत का कम स्तर हासिल करने के पश्चात्, विकास दर बढ़कर 2013-14 की पहली तिमाही में 4.7 प्रतिशत तक और इसके बाद 2013-14 की दूसरी तिमाही में 5.2 तक पहुंच गई, और गिरकर अगली दो तिमाहियों में 4.6 प्रतिशत रह गई। यह तथ्य कि ऐसा वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे धीमे पुनरुद्धार के बावजूद हुआ, उन घरेलू संरचनागत रुकावटों के निवारण के महत्व को दर्शाता है जिन्होंने उतार-चढ़ाव वाले और धीमे पुनरुद्धार को उत्पन्न किया है (बॉक्स 1.1)।

मुद्रास्फीति कम हो गई है लेकिन अभी भी संतोषजनक स्तर पर नहीं पहुंची है।

राजकोषीय मोर्चे और चालू खाता घाटा में सुधार दिखाई दे रहे हैं।

विकास में तेजी के आरंभिक संकेतों का बने रहना संरचनागत अडचनों को दूर करने पर निर्भर करता है।

बॉक्स 1.1 : संरचनागत रुकावटें क्या हैं?

भारत में वर्तमान आर्थिक गिरावट पर घरेलू संरचनागत घटकों के प्रभाव को अक्सर भारत में मांग की स्थितियों और दीर्घावधि वृद्धिकारी पूंजी परिणाम अनुपात को ध्यान में रखते हुए, स.घ.उ. के 30 प्रतिशत के लगभग नियत निवेश की दर और 5 प्रतिशत से कम की विकास दर के बीच ताल-मेल न होने के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। ऐसी समय श्रृंखला तकनीकों, जिनमें मंदी को संरचनागत और आवृत्ति घटकों के रूप में विनियोजित करने की कोशिश की गई है, के प्रयोग से दोनों की उपस्थिति को स्वीकृत किया गया है, हालांकि अनुपातों का आबंटन भिन्न है (चिनॉय एंड अजीज [2013]; आईएमएफ, डब्ल्यूईओ [2014]; मिश्रा [2013], अन्य)। संरचनागत रुकावटों का बड़ा प्रभाव निवेश दर में समनुरूप बड़ी गिरावट हुए बिना 5 प्रतिशत से कम की विकास दर का एक कारण है।

ये संरचनागत रुकावटें क्या हैं? इन अध्ययनों द्वारा यथाइंगित उनमें से कुछ प्रमुख रुकावटें निम्नवत् हैं:

- परियोजना प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने में आने वाली कठिनाइयों ने व्यापार करने की सुगमता को प्रभावित किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि परियोजनाओं में लंबी देरी हुई है और सम्पूर्ण निवेश अपर्याप्त रहे हैं।
- दोषपूर्ण लक्षित सब्सिडियों ने सरकारी निवेश के लिए राजकोषीय गुंजाइश को संकुचित और संसाधनों के आबंटन को विकृत किया है।
- छोटा विनिर्माण आधार, विशेषकर पूंजीगत वस्तुओं का, और विनिर्माण में कम मूल्य वर्धन। विनिर्माण विकास और निर्यातों को सरलीकृत प्रक्रियाओं, आसान ऋण और कम लेन-देन लागत के जरिये सुसाध्य बनाया जा सकता है।
- बड़े अनियमित क्षेत्र की उपस्थिति और नियमित क्षेत्र में अपर्याप्त श्रम समावेशन। अपेक्षित कौशल का अभाव एक महत्वपूर्ण कारण समझा जाता है।
- सुदृढ़ कृषि विकास के बिना उच्च अर्थिक विकास बनाए रखना कठिन है। कृषि में व्याप्त कम उत्पादकता इसमें रुकावट डाल रही है।
- सतत उच्च खाद्य मुद्रास्फीति उत्पन्न करने वाले संरचनागत घटकों पर काबू पाने की आवश्यकता है। विपणन के विभिन्न स्तरों में मध्यवर्ती संस्थाओं की अत्यधिक उपस्थिति, भण्डारण और प्रसंस्करण अवसंरचना की कमी, कृषि उत्पाद की अंतर-राज्य आवाजाही आदि से जुड़े मुद्दों को हल करने की जरूरत है।

संदर्भ

1. चिनॉय, साजिद जेड और जहांगीर अजीज (2013), 'वाय इज इंडियाज ग्रोथ एट ए 10-इयर लो? www.jpmmorganmarkets.com पर उपलब्ध है।
2. मिश्रा, प्राची (2013), 'हैज इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विदरड?' इकनॉमिक एंड पोलिटिकल लव वीकली, वाल्यूम XLVIII (15)।
3. इंटरनेशनल मॉनिटरी फण्ड (आईएमएफ) (2014), 'वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ)

क्षेत्रीय विकास की प्रवृत्तियां

1.6 अनुकूल मानसून की सहायता से, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र ने दीर्घावधि से चली आ रही लगभग 3 प्रतिशत की औसत (1999-2000 और 2012-13 के बीच) 2013-14 में 4.7 प्रतिशत की विकास दर हासिल की (सारणी 1.1)। तथापि, अन्य

क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (2स)	2012-13 (1स)	2013-14 (अ.अ.)
कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी	5.8	0.1	0.8	8.6	5.0	1.4	4.7
खनन तथा उल्खनन	3.7	2.1	5.9	6.5	0.1	-2.2	-1.4
विनिर्माण	10.3	4.3	11.3	8.9	7.4	1.1	-0.7
बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	8.3	4.6	6.2	5.3	8.4	2.3	5.9
निर्माण	10.8	5.3	6.7	5.7	10.8	1.1	1.6
व्यापार, होटल, परिवहन, तथा संचार	10.9	7.5	10.4	12.2	4.3	5.1	3.0
वित्त पोषण, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यवसाय सेवाएं	12.0	12.0	9.7	10.0	11.3	10.9	12.9
समुदाय, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	6.9	12.5	11.7	4.2	4.9	5.3	5.6
घटक लागत पर कुल स.घ.उ.	9.3	6.7	8.6	8.9	6.7	4.5	4.7

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: 1स: प्रथम संशोधित अनुमान, 2स: द्वितीय संशोधित अनुमान, अ.अ.: अनंतिम अनुमान।

अनुकूल मानसून कृषि विकास और विद्युत उत्पादन में सहायक रहा। औद्योगिक मंदी बरकरार रही।

सारणी 1.1 : (2004-2005) स्थिर कीमतों पर उत्पादन लागत पर स.घ.उ. वृद्धि (प्रतिशत)

कुछ क्षेत्रों में, यह गिरावट अधिक सुस्पष्ट और सामान्य से अधिक रही। खनन और उत्खनन गतिविधियों में 2011-12 से कमी आई है। खनन, कोयला और कच्चे पेट्रोलियम के दो प्रमुख घटक पिछले तीन-चार वर्षों से गतिहीन हैं। 2006-07 से 2009-10 की चार-वर्षीय अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में 7.1 प्रतिशत की औसत वृद्धि के पश्चात्, इसकी विकास दर 2013-14 में समाप्त होने वाले चार वर्षों के दौरान गिरकर 1.6 प्रतिशत रह गई। कोयला उत्पादन में गिरावट आंशिक रूप से विनियामक मुद्दों के चलते रही। कच्चे पेट्रोलियम की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2004-05 से 2013-14 के दौरान 1.2 प्रतिशत थी। चूंकि कोयला और पेट्रोलियम वैश्विक मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उनके अपर्याप्त उत्पादन ने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

1.7 विनिर्माण क्षेत्र के लिए पिछले दो वर्ष विशेष रूप से निराशाजनक रहे जब वृद्धि दर औसतन 0.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़ों के अनुसार, यह गिरावट बहुत व्यापक रही है। बुनियादी वस्तुओं की विकास दर में गिरावट 2013-14 में लगातार तीसरे वर्ष में भी बनी रही। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में भी 2011-12 से शुरुआत करते हुए तीसरे वर्ष भी गिरावट जारी रही। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 2013-14 में 12.2 प्रतिशत का संकुचन पाया गया। केवल मध्यवर्ती और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 2012-13 की तुलना में

बॉक्स 1.2 : रोजगार में व्याप्त रुझान

हालिया वर्षों में रोजगार-वृद्धि में हुई गिरावट चिन्ता का बड़ा सबब रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, श्रमिक दल में व्यक्तियों की संख्या (सामान्य स्थिति) 1999-2000 के 398 मिलियन से बढ़कर 2004-05 में 458 मिलियन हो गई जो पांच वर्षों में 15 प्रतिशत अथवा लगभग 60 मिलियन (कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में लगभग समान रूप से विभाजित) की वृद्धि है। यह संख्या और बढ़कर 2011-12 में 473 मिलियन हो गई जो सात वर्षों की अवधि में 15 मिलियन अथवा 3.3 प्रतिशत की वृद्धि बैठती है।

2004-05 और 2011-12 के बीच कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में श्रमिक दल में हुई गिरावट 36 मिलियन से अधिक थी। दूसरी तरफ, गैर-कृषि क्षेत्र में श्रमिक दल में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 51 मिलियन हो गई जिसमें उद्योग और सेवाओं ने क्रमशः 31 मिलियन और 20 मिलियन का योगदान किया। नीचे सारणी में सामान्य मूल और अनुषंगी स्थिति (यूपीएसएस) के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा अथवा श्रमिक दल (कार्यरत) के क्षेत्रीय संयोजन को दर्शाया गया है।

कुल रोजगार में प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा (प्रतिशत)	1999-2000			2004-05			2011-12		
कृषि और सहबद्ध	59.9			58.5			48.9		
उद्योग	16.4			18.2			24.3		
सेवाएं	23.7			23.3			26.9		

स्रोत: रंगराजन, सीमा और विबीश (2014)।

कृषि में रोजगार के हिस्से में हुई गिरावट अधिकतर देशों की विकास प्रक्रिया में देखी गई है। उद्योग में ही, रोजगार का अधिकांश 2004-05 और 2011-12 के बीच लगभग 25 मिलियन की वृद्धि के साथ निर्माण क्षेत्र में था। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में 6 मिलियन की वृद्धि हुई। 2004-05 और 2011-12 के बीच सेवा क्षेत्र में रोजगार में हुई लगभग 20 मिलियन की वृद्धि व्यापार, होटल और रेस्तरां क्षेत्र (4.7 मिलियन); परिवहन, भण्डारण और संचार (5.4 मिलियन); वित्तपोषण, भू-सम्पदा और व्यवसाय सेवाएं (5.3 मिलियन); और सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं (5 मिलियन) में कमोबेश एकसमान रूप से हुई। [रंगराजन, सीमा और विबीश (2014)]।

हालिया वर्षों में महिलाओं की श्रम दल और कार्य दल भागीदारी दर में भी गिरावट हुई है। अधिकतर विश्लेषकों ने, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में हुई तीव्र वृद्धि को ही इसकी वजह ठहराया है।

संदर्भ

रंगराजन सी०, सीमा और ई०एम० विबीश (2014), 'डेवल्पमेंट्स इन दि वर्कफोर्स बिटवीन 2009-10 एंड 2011-12, इकनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली, वाल्यूम XLIX (23)।

2013-14 में उच्चतर विकास दर दिखाई दी। 2004-05 और 2011-12 के बीच लगभग दोहरे अंक की विकास दर के बाद निर्माण क्षेत्र (इस अवधि में वह रोजगार का मुख्य स्रोत था, जैसाकि बाक्स 1.2 में देखा जा सकता है) ने पिछले दो वर्षों में वह रफ्तार खो दी। पूंजीगत वस्तुओं में देखी गई प्रवृत्तियों को मिलाकर, निर्माण गतिविधियों में आई गिरावट मंद हो गई कारोबार संवेदनाओं को प्रदर्शित करती है।

1.8 पिछले दो वर्षों में विनिर्माण विकास संबंधित आंकड़ों की व्याख्या सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि सीएसओ द्वारा इनमें संशोधन की संभावना बनी रहती है। विनिर्माण क्षेत्र में मूल्य वर्धन के प्रारम्भिक अनुमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित होते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे संशोधित अनुमान उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिक व्यापक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार 2011-12 के विनिर्माण की विकास दर, पूर्ववर्ती अनुमानित 2.7 प्रतिशत से दूसरे संशोधित अनुमानों (जनवरी, 2014 में जारी) को संशोधित करके 7.4 प्रतिशत की गई थी। इसका कारण यह है कि 2011-12 के लिए एएसआई के आंकड़े केवल 2013 के पूर्वार्द्ध में ही उपलब्ध हुए थे।

1.9 सेवाओं, मुख्य रूप से आंतरिक व्यापार, परिवहन और भण्डार क्षेत्रों में हुई गिरावट पण्य-उत्पादक क्षेत्रों में धन-प्रवाह की कमी के कारण थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में साधारण पुनरुत्थान संभवतः व्यवसाय सेवाओं के विकास में सहायक रहा 2013-14 में बैंक ऋण में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वित्तीय सेवाओं में उछाल को दर्शाता है।

1.10 विखंडित क्षेत्र-वार प्रवृत्तियों को स.घ.उ. में क्षेत्रीय हिस्से में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार बेहतर समझा जा सकता है, जैसाकि सारणी 1.2 में देखा जा सकता है। स.घ.उ. में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र का हिस्सा लगातार गिर रहा है। 1999-2000 और 2007-08 के बीच आठ वर्षों के दौरान, स.घ.उ. में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के हिस्से में 6.4 प्रतिशतांक की गिरावट हुई, जबकि उद्योग और सेवाओं का हिस्सा क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत बढ़ गया।

क्षेत्र	1999-2000	2007-08	2012-13	2013-14(अ)
कृषि और सहबद्ध	23.2	16.8	13.9	13.9
उद्योग	26.8	28.7	27.3	26.1
खनन और उत्खनन	3.0	2.5	2.0	1.9
विनिर्माण	15.0	16.1	15.8	14.9
पंजीकृत विनिर्माण	9.2	10.7	11.2	उ.न.
अपंजीकृत विनिर्माण	5.8	5.4	4.5	उ.न.
सेवाएं	50.0	54.4	58.8	59.9
व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	21.2	25.9	26.9	26.4
वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यवसाय सेवाएं	14.5	16.1	19.1	20.6
समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	14.4	12.4	12.8	12.9

सारणी 1.2 : स.घ.उ. में क्षेत्रीय हिस्सा (प्रतिशत)

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सीएसओ से परिकलित।

उ.न.-उपलब्ध नहीं अ: अनंतिम

टिप्पणी: उद्योग में बिजली, गैस और जलापूर्ति तथा निर्माण भी शामिल हैं जो सारणी में इंगित नहीं की गई हैं।

1.11 खनन और उत्खनन क्षेत्र में, पिछले कई वर्षों में स.घ.उ. हिस्से में लगातार गिरावट देखी गई जो व्यापक सुधारों के अभाव में उच्च विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी असमर्थता इंगित करती है।

1.12 विनिर्माण के मामले में, स.घ.उ. हिस्से में अधिकतर लाभ 2004-05 से 2007-08 के दौरान ऐसे समय पर हुआ जब कॉरपोरेट लाभों, बचतों और निवेश में सुदृढ़ विकास के साथ यह क्षेत्र 10 प्रतिशत से अधिक औसत वार्षिक दर पर विकास कर रहा था। पंजीकृत विनिर्माणों में गतिविधि भरपूर थी, जबकि अपंजीकृत विनिर्माणों का हिस्सा 2007-08 में समाप्त हो रहे चार वर्षों के दौरान अपरिवर्तित बना रहा। 2008-09 से 2012-13 के दौरान, पंजीकृत खंड के हिस्से में वृद्धि के बावजूद, विनिर्माण का हिस्सा कुल मिलाकर स्थिर रहा, क्योंकि अपंजीकृत निर्माण में केवल 3.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

1.13 सेवाओं का हिस्सा स.घ.उ. में लगातार वृद्धि कर रहा है, वह भी खासतौर पर 2004-05 से। लेकिन विस्तार की गति संतुलित नहीं थी। 2004-05 से सेवा क्षेत्र के विस्तार के प्रमुख प्रेरक संचार और बैंकिंग तथा बीमा थे इन क्षेत्रों की सुदृढ़ वृद्धि से ही मुख्यतः सेवा क्षेत्र का विस्तार 2010-11 के पश्चात भी हुआ। भू-सम्पदा और व्यवसाय सेवाओं के हिस्से को भी लाभ हुआ। ऐसी सेवाएं जिनमें मुख्य रूप से 2010-11 के पश्चात गतिहीनता/गिरावट आई, उनमें घरेलू कारोबार, होटल, और भण्डारण शामिल हैं। इन रोजगार-गहन क्षेत्रों की सतत् रफ्तार प्राप्त करने की असमर्थता, सेवा क्षेत्र में रोजगार में कम समनरूप वृद्धि का एक कारण हो सकती है।

1.14 कृषि और उद्योग में पर्याप्त रूप से उच्च विकास के अभाव के चलते, सेवाएं ऑटो-पायलेट प्रणाली पर सतत विकास को बनाए रखने में गम्भीर रूप से बाधाग्रस्त रहेंगी क्योंकि अधिकतर सेवाएं पण्य-उत्पादन क्षेत्रों, विशेषतः उद्योग के विकास पर निर्भर हैं (बॉक्स 1.3)।

सेवा क्षेत्र के विकास का पुनरुद्धार वस्तु उत्पादक क्षेत्रों के पुनरुद्धार पर आश्रित है। औद्योगिक पुनरुद्धार ही समग्र विकास की बहाली का आधार है।

बॉक्स 1.3 : अर्थव्यवस्था में आवक प्रवाह

अंतर-क्षेत्रीय संबंधों के अध्ययन का एक तरीका विभिन्न उद्योगों के बीच आवक प्रवाह के मैट्रिक्स की जांच करना है। निम्नलिखित सारणी सीएसओ द्वारा जारी नवीनतम उपलब्ध आवक-जावक सारणियों (2007-08) से तैयार की गई है। इसमें निहित सूचना यद्यपि थोड़ी सी पुरानी है, फिर भी अंतर-क्षेत्रीय संबंधों की स्थिति को इंगित करती है।

अर्थव्यवस्था में अंतर-उद्योग आवक प्रवाह (प्रतिशत में)

	कृषि और सहबद्ध-क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र आवक	सेवा-क्षेत्र आवक
कृषि और सहबद्ध	55.3	7.7	7.5
उद्योग	21.4	68.2	45.1
सेवाएं	23.3	24.1	47.5

अर्थव्यवस्था में कुल आवकों का योगदान (प्रतिशत में)

कृषि और सहबद्ध	11.8
उद्योग	59.6
सेवाएं	28.6

स्रोत: सीएसओ की आवक-जावक सारणियों पर आधारित आंतरिक गणनाएं

उपर्युक्त सारणी का ऊपरी भाग यह सूचित करता है कि कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों की कुल आवक आवश्यकता में से, 55.3 प्रतिशत का अंशदान इसी क्षेत्र द्वारा किया गया था, जबकि उद्योग और सेवाओं ने क्रमशः 21.4 प्रतिशत और 23.3 प्रतिशत का अंशदान किया। उद्योग के लिए आवश्यक कुल आवक के दो-तिहाई से अधिक हिस्सा स्वयं उद्योग से आया है, जबकि लगभग एक-चौथाई सेवा क्षेत्र से आया। सेवा क्षेत्र के लिए आधे से ज्यादा आवक उद्योग और कृषि क्षेत्रों से आए। सारणी में सेवा क्षेत्र में स्थायी आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने में औद्योगिक क्षेत्र के महत्व को मुख्य रूप से रेखांकित किया गया है। जैसाकि सारणी के निचले भाग से यह स्पष्ट है, कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कार्यरत कुल आवकों का 11.8 प्रतिशत बैठा, जबकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की भूमिका क्रमशः 59.6 प्रतिशत और 28.6 प्रतिशत रही। अतः औद्योगिक क्षेत्र में सतत पुनरुत्थान ही सतत् विकास का केन्द्र है।

तिमाही रुझान

1.15 तिमाही स.घ.उ. आंकड़े वर्ष के भीतर उतार-चढ़ाव बिन्दुओं की पहचान करने में सहायक हो सकते हैं (चित्र 1.2)। विकास में आई अपेक्षाकृत दीर्घावधिक मंदी का वर्तमान घटनाक्रम 2011-12 की पहली तिमाही में शुरू हो गया था, जबकि विनिर्माण की वृद्धि में गिरावट 2011-12 की दूसरी तिमाही में शुरू हुई। खनन और उत्खनन में गिरावट 2010-11 की अन्तिम तिमाही में सामने आई और यह प्रवृत्तियां अभी तक बनी हुई हैं। बिजली, गैस और जलापूर्ति में 2012-13 की तुलना में 2013-14 में कुछ उच्चतर वृद्धि देखी गई जो मुख्यतः जलाशयों में बेहतर जल उपलब्धता के कारण पनबिजली स्रोतों से अधिक बिजली सृजन के चलते है।



चित्र 1.2 : कारक लागत पर सघड में तिमाही वार वृद्धि (2004-05 की कीमतें)

स्रोत: (सीएसओ)

सकल मांग

1.16 अर्थव्यवस्था की सकल मांग में कुल अंतिम उपभोग और निवेश के साथ-साथ व्यापारिक माल के निवल निर्यातों (निर्यात रहित आयात) एवं कारक भिन्न सेवाएं होती हैं। राष्ट्रीय लेखा निर्धारण में चालू खाता शेष से भी घरेलू बचतों एवं घरेलू निवेश के बीच के अंतर का आंकलन होता है। इससे उस अंतर की सीमा सूचित होती है जिसे विदेशी बचतों की मदद से पाटे जाने की जरूरत है।

1.17 स्थिर बाजार कीमतों (2004-05) पर स.घ.उ. के अनुसार मापित सकल मांग के अनुसार वर्ष 2013-14 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जो पिछले वर्ष में 4.7 प्रतिशत रही थी। निजी अंतिम उपभोग में वृद्धि जो 2003-04 से 2011-12 के दौरान औसतन 7.8 प्रतिशत थी, गिरकर 2012-13 में 5.0 प्रतिशत और 2013-14 में और 4.8 प्रतिशत रह गई। वास्तविक रूप में, नियत निवेश 2011-12 और 2013-14 के बीच शायद ही बढ़ पाया है। स.घ.उ. के हिस्से के अनुसार, 2012-13 और 2013-14 में मांग पक्ष संबंधी अधिकतम उल्लेखनीय परिवर्तन स.घ.उ. और सकल नियत पूंजीगत निर्माण के अनुपात में 2.1 प्रतिशत अंकों की अचानक गिरावट होना रहा है। इस प्रकार, 2013-14 में सकल मांग की वृद्धि दर में बढ़त का मुख्य श्रेय निवल निर्यातों के उच्च स्तर (निर्यातों और आयातों के बीच के अंतर में कटौती के रूप में प्रतिबिंबित जैसाकि सारणी 1.3 में देखा जा सकता है) को जाता है। सकल मांग के प्रधान घटकों का विश्लेषण आने वाले खंडों में किया गया है।

उपभोग

1.18 अंतिम उपभोग व्यय का अनुमान सरकारी और निजी कंपनियों के लिए अलग-अलग किया जाता है। सघड में अंतिम उपभोग का हिस्सा 1950 के दशक से

2013-14 में समग्र मांग में मामूली सुधार हुआ।

मद	2011-12 (2स)	2012-13 (1स)	2013-14 (अ.अ.)
(i) टीएफसीई	68.5	68.8	68.9
निजी	57.1	57.1	57.1
सरकारी	11.4	11.8	11.8
(ii) जीसीएफ	35.5	34.8	अनु.
एफसीएफ	31.8	30.4	28.3
स्टॉक में परिवर्तन	1.9	1.7	1.6
मूल्यवान वस्तुएं	2.7	2.6	1.5
(iii) निर्यात	23.9	24.0	24.8
(iv) घटाए आयात	30.2	30.7	28.4

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

टिप्पणियां : टीएफसीई: कुल अंतिम उपभोग व्यय, जीसीएफ: सकल पूंजी निर्माण, एफसीएफ: नियत पूंजी निर्माण, 1स: प्रथम संशोधित अनुमान, 2स: द्वितीय संशोधित अनुमान, अ.अ.: अन्तिम अनुमान। विसंगतियों और पूर्णांकन के कारण (i) से (iv) तक संभवतः 100 का आंकड़ा न प्राप्त हो सका।

सारणी 1.3 : वर्तमान बाजार कीमतों पर स.घ.उ. के घटक और स.घ.उ. में हिस्सा

निरंतर कम होता रहा है जो मुख्यतः निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) के हिस्से में कमी के रूप में दीख रहा है। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि उच्च आय-स्तरो के परिणामस्वरूप परिवारों की बचतें भी अधिक हो गयी हैं और उपभोग का हिस्सा भी घट गया है। 1980 के दशक के आरंभ तक निर्यातों में आई उदासीनता के चलते ऐसा होना अनिवार्य भी था क्योंकि अधिक विकास कराने के लिए अपेक्षित निवेश की बढ़ती राशि घरेलू उच्च बचतों से ही प्राप्त होनी थी। वार्षिक वृद्धि में उच्च उतार-चढ़ावों के बावजूद, सघउ के अनुपात के रूप में सरकारी उपभोग व्यय में, 1980 के दशक से उल्लेखनीय संगति देखी गई है (सारणी 1.4)।

1.19 कुल अंतिम उपभोग में खाद्य मदों, पेय पदार्थ और तंबाकू समूह के वास्तविक संदर्भ में हिस्से में 2004-05 से 2012-13 तक नौ वर्षों में सघउ के 9.5 प्रतिशतांक की कमी हो गयी। किन्तु, सांकेतिक रूप में, (सारणी 1.5) यह कमी वास्तव में भी गिरावट की केवल लगभग आधी थी, जो इस अवधि में इन उत्पादों की अपेक्षाकृत उच्च कीमतों को दर्शाती है।

1.20 'खाद्य, पेय पदार्थ और तंबाकू' समूह के अलावा, सकल किराया, ईंधन और बिजली, चिकित्सा परिचर्या और स्वास्थ्य सेवाओं, तथा परिवहन और दूरसंचार सेवाओं के हिस्से में भी गिरावट हुई, जबकि विशालतम बढ़त 'अन्य विविध सेवाओं' में दर्ज की गई जिसमें बैंकिंग प्रभार, विधिक सेवाएं, व्यवसाय सेवाएं और जीवन बीमा शामिल हैं। सेवाओं के उपभोग के प्रति प्रगामी झुकाव और गैर-टिकाऊ मालों, खासकर खाद्य मदों से दूर हटने की प्रवृत्ति देखी गई है।

मद	वर्तमान बाजार मूल्यों का अनुपात	
	2004-05	2012-13
खाद्य, पेय पदार्थ और तंबाकू	40.0	35.2
कपड़े और जूते	6.6	7.2
सकल किराया, ईंधन और बिजली	13.8	13.1
फर्नीचर, फर्निशिंग उपकरण एवं सेवाएं	3.4	3.9
चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं	5.0	3.6
परिवहन और संचार	19.3	17.4
मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक सेवाएं	3.0	2.5
वैयक्तिक देख रेख और संबंधित सेवाएं	2.7	3.8
प्रकीर्ण वस्तुएं एनईसी	1.6	1.8
अन्य प्रकीर्ण सेवाएं	4.7	11.5

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

निवेश

1.21 निवेश में नियत पूंजी निर्माण, मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति, और भूल-चूकों के लिए समायोजित स्टॉक और वस्तु सूचियों में फेर-बदल शामिल हैं। निवेश दर (सघउ में निवेश का अनुपात) 1990-91 से 2003-04 की अवधि में औसतन 24.5 प्रतिशत थी (सारणी 1.6)। वर्ष 2004-05 ऐसा विशिष्ट वर्ष रहा जब पहली बार निवेश दर 30 प्रतिशत से अधिक हो गई। 2004-05 और 2012-13 के बीच निवेश दर का औसत 35.4 प्रतिशत था जो 2007-08 में 38.1 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई थी। इस निवेश दर का औसत 2004-05 से 2007-08 की उच्च वृद्धि के काल में 35.3 प्रतिशत और 2008-09 तथा 2012-13 के बीच 35.5 प्रतिशत था। 2012-13 में 34.8 प्रतिशत की निवेश दर इन दो उप-अवधियों की औसत निवेश दर से कमतर है।

1.22 सकल नियत निवेश की दर, जो कुल निवेश का अधिकांश होता है, की दर में 2004-05 से उल्लेखनीय वृद्धि हुई, 2007-08 में अधिकतम हुआ और उसके बाद

अर्थव्यवस्था की स्थिति

हालिया वर्षों में सघउ में निजी उपभोग के हिस्से में गिरावट हुई है।

मद	1980s	1990s	2000s	2010-11 से 2013-14
टीएफसीई	85.8	77.5	71.6	68.4
पीएफसीई	74.5	65.9	60.3	56.8
जीएफसीई	11.3	11.6	11.3	11.6

स्रोत: सीएसओ

टिप्पणी : 2013-14 हेतु आंकड़े अंतिम हैं। जीएफसीई: सरकारी अंतिम खपत व्यय, पीएफसीई: निजी अंतिम उपभोग व्यय और टीएफसीई: कुल अंतिम खपत व्यय है।

सारणी 1.4 : वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. में अंतिम खपत का हिस्सा (प्रतिशत)

सारणी 1.5 : घरेलू बाजार में निजी अंतिम उपभोग व्यय में वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों का हिस्सा (कुल का प्रतिशत)

नियत निवेश दर में 2013-14 में तेजी से गिरावट हुई।

₹	1990-91 से 1999-2000	2000-01 से 2003-04	2004-05 से 2007-08	2008-09 से 2012-13	2012-13	2013-14
I. सकल नियत पूंजी निर्माण	23.1	24.0	30.8	31.4	30.4	28.3
निर्माण	12.1	14.2	16.9	17.7	17.5	उ.न.
मशीनरी और उपस्कर	11.0	9.8	13.9	13.8	12.9	उ.न.
(i) सरकारी क्षेत्र निर्माण	8.6	6.7	7.6	7.9	7.8	उ.न.
मशीनरी और उपस्कर	4.7	4.3	5.0	5.3	5.4	उ.न.
(ii) निजी कारपोरेट क्षेत्र निर्माण	6.7	5.5	11.9	9.8	8.5	उ.न.
मशीनरी और उपस्कर	1.0	1.3	3.5	2.5	2.4	उ.न.
(iii) घरेलू निर्माण	7.9	11.8	11.3	13.7	14.1	उ.न.
मशीनरी और उपस्कर	6.4	8.6	8.4	9.9	9.7	उ.न.
II. स्टाकों में परिवर्तन	0.7	0.5	3.2	2.4	1.7	1.6
III. मूल्यवान वस्तुएं	—	0.7	1.2	2.1	2.6	1.5
IV. कुल निवेश*	24.3	25.0	35.3	35.5	34.8	उ.न.

स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सीएसओ में निहित सूचना से परिकलित।

टिप्पणी : *कुल निवेश, भूल-चूक के कारण तीनों घटकों के जोड़ के समान नहीं हो सकता।

सामान्यतः घट गया। सीएसओ द्वारा जारी 2013-14 के अंतिम अनुमानों के अनुसार, 2013-14 के स.घ.उ. में नियत पूंजी निर्माण का अनुपात का 2012-13 के अनुपात से 2.1 प्रतिशत अंक कम था। स.घ.उ. में कीमती वस्तुओं का अनुपात उस अवधि में भी आमतौर पर बढ़ गया जब नियत निवेश कम हो गए थे और इस प्रकार निवेश की समग्र दर लगभग 35 प्रतिशत पर रही। स्टाकों में होने वाले परिवर्तन आमतौर पर व्यापक घट-बढ़ के कारण होते हैं।

1.23 2004-05 और 2007-08 के बीच की बढ़ोतरी की अवस्था के दौरान समग्र निवेश में अधिकांश बढ़त का कारण निजी कारपोरेट क्षेत्र के निवेश में हुई बढ़त से स्पष्ट होता है। इसी क्षेत्र का हाथ निवेश दर की वर्तमान गिरावट में अधिकतम रहा (सारणी 1.7)। (बॉक्स 1.4 में निवेश में गिरावट के सटीक कारणों की जांच की गई है)। निजी कारपोरेट क्षेत्र के निवेश में वृद्धि 2004-05 से 2007-08 तक की अवधि में विशेष रूप से तीव्र रही, जब इसका औसत वर्तमान कीमतों पर वार्षिक रूप से 48.1 प्रतिशत था। इसकी वृद्धि दर 2008-09 से 2012-13 के दौरान गिरकर 3.4 प्रतिशत रह गई। सरकारी क्षेत्र का निवेश भी जो पूर्ववर्ती अवधि में 23.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा, बाद में मंद हो गया। इसके विपरीत, पारिवारिक निवेश में वृद्धि 2004-05 से 2007-08 के दौरान में वार्षिक औसत 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 से 2012-13 में औसत 23.5 तक हो गयी। संस्थाओं द्वारा निवेश के पैटर्न सारणी 1.7 में दिखाए गए हैं।

क्षेत्र	1990-91 से 1999-2000	2000-01 से 2003-04	2004-05 से 2007-08	2008-09 से 2012-13	2012-13
सरकारी	8.8	6.8	8.1	8.6	8.1
निजी कारपोरेट	7.0	5.6	13.9	11.1	9.2
घरेलू	8.0	12.1	11.9	14.1	14.8
कुल निवेश*	24.3	25.0	35.3	35.5	34.8

स्रोत : सीएसओ

टिप्पणी : कुल निवेश भूल-चूक और मूल्यवान वस्तुओं के कारण तीनों घटकों के जोड़ के समान नहीं होगा।

सारणी 1.6 : वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में निवेश के घटक (प्रतिशत)

कम हो गई निजी कारपोरेट निवेश दर समग्र निवेश दर में गिरावट का मुख्य कारण है।

सारणी 1.7 : वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में संस्था के स्वरूप के अनुसार निवेश (प्रतिशत)

बाक्स 1.4 : निवेश-मंदी: सटीक कारक

क्या यह अनुमानित या वास्तविक ब्याज दर है जिससे निवेश दर में कटौती पर प्रकाश पड़ता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन से जिसका शीर्षक है "रीयल इन्टरस्ट रेट इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ- व्हाट दि एम्पिरिकल एविडेन्स फॉर इंडिया सजेस्ट्स" से पता चलता है कि यह अनुमानित दर नहीं, परंतु वास्तविक ब्याज दर है जिससे निवेश संबंधी निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है। किंतु कुछ लोग यह तर्क करते हैं कि हालिया वर्षों में निवेशगत वृद्धि कम वास्तविक ब्याज दरों के बावजूद कमजोर हो गयी है। इस अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि कम वास्तविक ब्याज दर से निवेश और संवृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है बशर्ते कि यह उच्च मुद्रास्फीति के रास्ते प्राप्त न की जाए। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि अनुमानित ब्याज दर फर्म के स्तर पर निवेश की आयोजना के लिए वास्तविक ब्याज दर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में निवेश के निर्णयों को स्पष्ट करने में कंपनी के ऋण-इक्विटी अनुपात की भूमिका को भी इंगित किया गया है। अत्यंत ऋण आश्रित क्षेत्र में, जैसे कि अवसंरचना में, इक्विटी पर प्रतिफल की अपेक्षित दर अधिक रह सकती है, परंतु इक्विटी पर वास्तविक प्रतिफल प्राप्त करना ब्याज लागतों और नकदी प्रवाहों के रूख का कार्य होगा। यदि ब्याज लागतें बढ़ती हैं और संभावित नकदी प्रवाह घटता है तो पर्याप्त इक्विटी पूंजी के प्रवाह का इंतजाम करना कठिन हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कुछ निर्धारित निवेश परियोजनाएं स्थगित की जा सकती हैं। कंपनियों के नकदी प्रवाहों में कमी का कारण ये हो सकते हैं: (क) शिथिल मांग की स्थितियां (ख) कमजोर कीमत निर्धारण शक्ति (ग) उच्च निविष्टि लागत (घ) आदेशों के प्रदाय के बाद उत्पाद की सुपुर्गामी में विलंब।

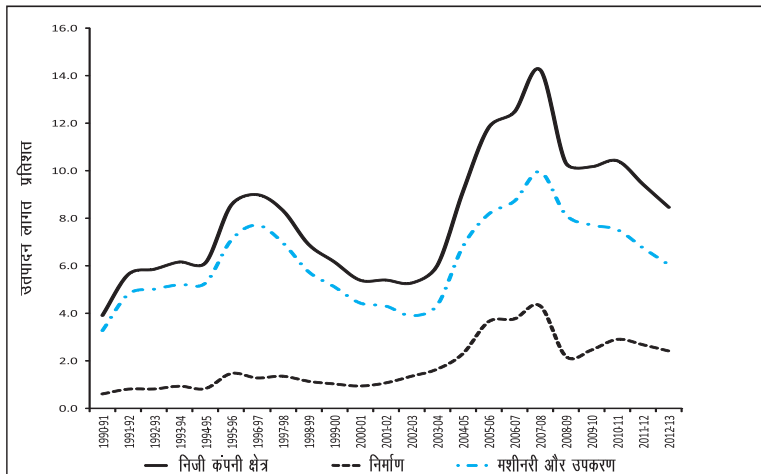
2007-08 के बाद निवेशगत वृद्धि में आंशिक मंदी का कारण भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों से उत्पन्न नीतिगत अनिश्चितता, विलंबित पर्यावरणगत स्वीकृतियों, अवसंरचनागत अवरोधों, कोयले की प्राप्ति में आने वाली समस्याओं, चयनित क्षेत्रों में खनन पर रोक आदि को ठहराया जा सकता है। टोकुका (2012) के अनुसार अधिक हो गई वैश्विक अनिश्चितता के साथ-साथ उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति (उच्च राजकोषीय घाटे से अंशतः उत्पन्न) के परिणामस्वरूप कंपनी निवेश में मंदी हुई होगी। निवेश में मंदी के कारण को व्यवसाय के लस्त-पस्त माहौल और व्यवसाय में कमजोर आत्मविश्वास की पृष्ठभूमि में भी स्पष्ट किया जा सकता है।

आनंद और तुलिन (2014) का सुझाव है कि यद्यपि अनुमानित ब्याज दरों की तुलना में वास्तविक ब्याज दरों से सकल निवेश क्रियाकलाप को बेहतर ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है, तथापि उनसे स्पष्टीकृत अधोमुखी निवेश का केवल एक तिहाई भाग ही बैठते हैं। उनका निष्कर्ष यह है कि मानक वृहद् वित्तीय परिवर्तनीय कारणों से हालिया निवेशगत मंदी की पूर्णतः व्याख्या नहीं होती एवं बढ़ी हुई अनिश्चितता और व्यवसाय के घटते आत्मविश्वास ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अनुसार अनुमानित ब्याज दरों में कमी करने से ब्याज के बोझ से अल्पकालिक राहत मिल सकती है, परंतु मध्यकालिक संदर्भ में अर्थव्यवस्था में नाममात्र की शिथिलता लाने के साथ अल्प दरों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ेगी तथा निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। अतः संरचनागत सुधार तथा आपूर्ति पक्ष के गत्यावरोध का समाधान निवेश को प्रोत्साहित करने की मुख्य कुंजी है।

संदर्भ

1. "आरबीआई (2013) रीयल इन्टरस्ट रेट इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ: व्हाट दि एम्पिरिकल एविडेन्स फॉर इंडिया सजेस्ट्स?" www.rbi.org. पद पर उपलब्ध है।
2. टोकुका, किची (2012) "डज दि बिजनेस एन्वायरनमेंट अफेक्ट कारपोरेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया?" आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यू पी/12/70
3. आनंद राहुल और बी तुलिन (2014) "डिस्पेंडिंग इंडियाज इन्वेस्टमेंट स्लोडाउन" आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यू पी/14/47

1.24 2004-05 और 2007-08 के बीच की उच्च वृद्धि की अवस्था में, निजी कारपोरेट क्षेत्र के नियत निवेश का मशीनरी तथा उपस्कर खंड का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में करीब-करीब दोगुना हो गया (सारणी 1.6)। इसी प्रकार निर्माण क्षेत्र के हिस्से में भी तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। विगत तीन-चार वर्षों में नियत निवेश दर में गिरावट का मुख्य कारण निजी कारपोरेट क्षेत्र के मशीनरी और उपस्कर खंड के हिस्से में आई गिरावट को ठहराया जा सकता है। (चित्र 1.3)।



चित्र 1.3 : निजी कारपोरेट क्षेत्र और इसके घटकों में सघट के अनुपात के रूप में सकल नियत निवेश।

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

अर्थव्यवस्था की स्थिति

1.25 निजी कारपोरेट क्षेत्र के नियत निवेश के निर्माण खंड में आई गिरावट, मशीनरी और उपस्कर खंड में हुई गिरावट के मुकाबले अपेक्षाकृत कम रही है। ऐसा इस तथ्य के कारण हो सकता है कि निवेश का मशीनरी और उपस्कर खंड, निर्माण खंड की तुलना में व्यापार की मनोदशाओं में अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से प्रभावित होता है। निर्माण की लंबी अवधि का तात्पर्य है कि जब किसी परियोजना का प्रारंभ/स्थगन किया जाता है तो व्यवसाय की मनोदशाओं में बदलाव होने से उसे बंद करने/पुनः क्रियाशील करने में लंबा समय लगता है। मंदी के दौरान मशीनरी और उपस्कर में निवेश करने के परिणामस्वरूप इसका कम उपयोग और प्रायः टूट फूट (अप्रचलन) भी हो सकता है। निर्माण क्रियाकलाप इन समस्याओं से बहुत कम प्रभावित होता है।

मूल्यवान वस्तुएं

1.26 कीमती वस्तुओं में ऐसी आस्तियां शामिल हैं जो प्रधानतः मूल्य भंडार के रूप में रखी जाती हैं। मूल्यवान वस्तुओं के निवल अर्जन में कीमती सामान, रत्न और पत्थर, चांदी, सोना, प्लेटिनम और सोने-चांदी के आभूषण शामिल हैं। मूल्यवान वस्तुओं के सकल स्वामित्व में हुए परिवर्तन का संभवतः अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता पर संभवतः कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता।

1.27 मूल्यवान वस्तुओं के अर्जन पर हालिया वर्षों में हुई उल्लेखनीय घट-बढ़ों का असर रहा है। सघड में उनका हिस्सा 2007-08 के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 2.6 प्रतिशत हो गया और बाद में गिरकर 2013-14 में 1.5 प्रतिशत रह गया। सोने चांदी के आयातों का मूल्य 2010-11 में 42.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2012-13 में 55.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बहाल करने और सीएडी घटाने के लिए सरकार ने अगस्त, 2013 में सोने-चांदी पर आयात शुल्कों में वृद्धि करने सहित कतिपय उपायों की घोषणा की। इन उपायों के परिणामस्वरूप सोने चांदी के आयात के सम्मिलित मूल्य में अमरीकी डालर के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत तक गिरावट आई जो स.घ.उ. में मूल्यवान वस्तुओं के हिस्से में गिरावट के रूप में बड़े पैमाने पर प्रतिबिम्बित हुई है।

निवल निर्यात

1.28 राष्ट्रीय लेखों में निवल निर्यात, वस्तुओं और कारक-भिन्न सेवाओं के निर्यात तथा वस्तुओं और कारक भिन्न सेवाओं के आयात के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्णतः समुत्थान होना अभी दूर है, तथापि, वैश्विक आर्थिक सुदृढ़ीकरण के प्रारंभिक संकेतों से भारत को निर्यातों में आंशिक समुत्थान करने में मदद मिली। दूसरी ओर कैंड पर काबू पाने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों से आर्थिक मंदी के रहते हुए मुख्यतः अनावश्यक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करते हुए आयातों को घटाने में मदद मिली है। सघड में निर्यातों का हिस्सा 2012-13 में 24.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 24.8 प्रतिशत हो गया जबकि आयातों का हिस्सा 30.7 प्रतिशत से घटकर 28.4 प्रतिशत रह गया। इसके परिणामस्वरूप निवल निर्यातों में सघड के 3.1 प्रतिशत अंकों तक सुधार हुआ।

आयातों में हुई गिरावट के साथ निर्यातों में हुई साधारण वृद्धि से निवल निर्यात स्थिति सुधारने में मदद मिली।

लोक वित्त

1.29 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम लागू किए जाने के बाद से केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा घटकर 2007-08 में स.घ. उ. के 2.5 प्रतिशत तक लाया गया जो स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के प्रारंभिक लक्ष्य से कम था। 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप सकल मांग बढ़ाने और वृद्धि दर उठाने के लिए राजकोषीय शेष राशियों को जानबूझकर विस्तृत किया गया। 2010-11 में क्रमिक राजकोषीय दृढ़ीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गई।

सरकार ने अक्टूबर 2012 में संशोधित राजकोषीय समेकन योजना का प्रवर्तन किया। इसमें 2013-14 में सघउ के 4.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करना निर्धारित था और उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 0.6 प्रतिशत अंक के सुधार के जरिए 2016-17 तक का राजकोषीय घाटा सघउ के 3.0 प्रतिशत तक लाना लक्षित था।

1.30 स.घ.उ. के 4.8 प्रतिशत के बजट विहित लक्ष्य की तुलना में 2013-14 में स.घ.उ. के 4.5 प्रतिशत का अपेक्षाकृत कम राजकोषीय घाटा राजकोषीय समेकन पर निरंतर जोर दिए जाने का सूचक है। कर राजस्वों और विनिवेश प्राप्ति में कमी आने और सब्सिडियों और ब्याज तथा पेंशन भुगतानों पर बजट विहित से अधिक राशि खर्च करने से राजकोषीय समेकन का लक्ष्य प्रधानतः बजट विहित स्तरों के मुकाबले व्यय में कमी करके हासिल किया गया।

1.31 केंद्र के राजकोषीय घाटे के संदर्भ में इसके निष्पादन का मोटे तौर पर यह संकेत है कि वृहत् आर्थिक अनिश्चितताओं एवं विश्व में कच्चे तेल की उच्च कीमतों के बावजूद, राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त किए गए। वर्तमान में प्रचलित स्तरों से ऊपर कर सघउ अनुपात को ले जाना अंततोगत्वा राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यय पर एक निश्चित न्यूनतम स्तर से अधिक दबाव डालने का प्रतिकूल असर हो सकता है।

1.32 2008-09 के बाद से केन्द्रीय राजस्व घाटे में बढ़त कराने वाले प्रधान कारणों में से एक कारण सब्सिडियों का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना रहा है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, 2013-14 में प्रधान सब्सिडियों का योग 2,47,596 करोड़ रुपए था। सब्सिडियों में तीव्र वृद्धि हुई है जो 2007-08 में स.घ.उ. के 1.42 प्रतिशत से बढ़ती हुई 2012-13 में स.घ.उ. के 2.56 प्रतिशत हो गई, 2013-14 (सं.अ.) के लिए यह स.घ.उ. का 2.26 प्रतिशत थी। खाद्य सब्सिडी में इजाफा होता रहा है जिसकी वजह भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई खरीद की आर्थिक लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्नों के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में बढ़ता अंतर है। हालांकि उर्वरक सब्सिडी का अंशतः विनियंत्रण हुआ है, यूरिया की कीमतें अभी सीमा के अंदर हैं; इसी प्रकार पेट्रोल की कीमतें विनियंत्रित कर दी गई हैं तथा डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की मासिक बढ़ोतरी करायी जा रही है। प्रति माह प्रति परिवार को दिए जाने वाले सहायता प्राप्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलिंडरों की अधिकतम संख्या अप्रैल 2014 से 9 से बढ़ाकर 12 तक कर दी गई है। इसके अलावा, रिसाव भी सब्सिडी का कुल बोझ बढ़ाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। खाद्य मदों के मामले में, योजना आयोग के लक्षित पीडीएस (2005) संबंधी निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन में कहा गया है कि गरीब जनता को वितरित अन्न के प्रत्येक एक किलोग्राम के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय पूल से 2.4 कि.ग्रा. अन्न जारी किया। वर्तमान तंत्र के जरिए पीडीएस के खाद्यान्नों की सुपुर्दगी की लागत को लेकर इसके गंभीर निहितार्थ हैं।

1.33 उच्च राजकोषीय घाटे की परिणति प्रायः सरकारी ऋण के बढ़ने में होती है। भारत में केंद्र सरकार की देयता स.घ.उ. का अनुपात 2002-03 के 61.6 प्रतिशत से घटकर 2013-14 (सं.अ.) में 49.4 प्रतिशत रह गया। इस अनुमान में कमी का श्रेय अनुमानित ब्याज दरों की तुलना में उच्च अनुमानित स.घ.उ. वृद्धि दर को जाता है। कुल सरकारी ऋण में से आंतरिक ऋण 95.5 प्रतिशत बैठता है जबकि विदेशी ऋण (खाता मूल्य पर) यथावत है।

घरेलू बचतें

1.34 सकल घरेलू बचतों के अनुमान के लिए अर्थव्यवस्था को तीन बड़े संस्थागत क्षेत्रों—सरकारी, निजी कारपोरेट और परिवारों में विभाजित किया गया

राजकोषीय समेकन का लक्ष्य 2013-14 में बजट विहित व्यय से कम स्तर पर प्राप्त हुआ।

कर-स.घ.उ. का अनुपात बढ़ाना तथा सब्सिडी में और अधिक सुधार करना राजकोषीय समेकन हेतु अनिवार्य है।

सारणी 1.8 : वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत दर और इसके घटक।

मद	1990s	2000s	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	ऐतिहासिक उच्च*
सकल घरेलू बचतें	23.0	30.6	36.8	32.0	33.7	33.7	31.3	30.1	36.8 (2007-08)
घरेलू क्षेत्र	17.7	23.1	22.4	23.6	25.2	23.1	22.8	21.9	25.2 (2009-10)
वित्तीय	9.6	10.8	11.6	10.1	12.0	9.9	7.0	7.1	12.0 (2009-10)
भौतिक	8.0	12.3	10.8	13.5	13.2	13.2	15.8	14.8	15.8 (2011-12)
निजी कारपोरेट क्षेत्र	3.6	6.3	9.4	7.4	8.4	8.0	7.3	7.1	9.4 (2007-08)
सरकारी क्षेत्र	1.6	1.2	5.0	1.0	0.2	2.6	1.2	1.2	5.6 (1976-77)

स्रोत : सीएसओ

टिप्पणी : *कोष्ठकों में आंकड़े उस वर्ष से संबंधित हैं जिसमें यह उच्चतम दर्ज किया गया था।

है। बचत दर 2003-04 में 29.0 प्रतिशत से बढ़कर, जो तब तक की उच्चतम थी, 2007-08 में 36.8 प्रतिशत हो गई, जो अब तक की ऐतिहासिक वृद्धि थी (सारणी 1.8)।

1.35 सकल बचत दर 36.8 प्रतिशत के उच्च स्तर से, गिर कर 2012-13 में स.घ. उ. का 6.7 प्रतिशतांक रह गई। अधिकांश गिरावट का कारण निजी कारपोरेट क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को दिया जा सकता है। यद्यपि निजी क्षेत्र में गिरावट मुख्यतः उद्योग क्षेत्र में कम वृद्धि के चलते और कम लाभ मार्जिनों के कारण हुई, तथापि स.घ.उ., में कम सरकारी बचतों के अनुपात का कारण गैर-विभागीय सरकारी उद्यमों की कम बचतें और सरकारी प्राधिकरणों की बृहतर निर्बचतें थीं। पारिवारिक बचतें वित्तीय बचतों और भौतिक आस्तियों में बचतों का जोड़ होती हैं। पारिवारिक बचत दर 2000-01 एवं 2006-07, के बीच स.घ.उ. के औसतन लगभग 23 प्रतिशत पर स्थिर हो चुकी थी। इसके पश्चात्, इसमें अस्थिरता आ गई। 2007-08 से 2011-12 की अवधि में परिवारों की बचतों में भारी संघटनात्मक परिवर्तन वित्तीय बचतों की अपेक्षा भौतिक बचतें करने में देखा गया। निर्माण, मशीनरी तथा उपस्कर में निवेश सहित परिवारों की भौतिक आस्तियों में निवल वृद्धि और भण्डारों में परिवर्तन भौतिक आस्तियों में परिवारों की बचत का द्योतक है। 2012-13 में निर्माण गतिविधि की वृद्धि में महत्वपूर्ण कमी होने के साथ, परिवारों द्वारा की जाने वाली भौतिक बचत दरों में गिरावट आई। 2013-14 में निर्माण क्षेत्र की मजबूती से उठ पाने में नाकामी के साथ-साथ, मशीनरी और उपस्कर क्षेत्र में आई निष्क्रियता यह इंगित करती है कि वर्ष में पारिवारिक भौतिक बचतों में हुई वृद्धि पस्त रही है।

1.36 गैर-प्रचालन अधिशेष घाटा के लिए समायोजित निजी कारपोरेट क्षेत्र के प्रतिधारित लाभ और मूल्यहास इसकी सकल बचतें हैं, जिनमें 2002-03 के पश्चात् तेजी से वृद्धि हुई और यह 2007-08 तक 9 प्रतिशत से अधिक हो गई। यह कारपोरेट लाभप्रदता में महत्वपूर्ण और समनुरूप सुधार था जिससे निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत दर 1980 के दशक के दौरान के 2 प्रतिशत से कम के स्तर से बढ़ती हुई 2007-08 में 9 प्रतिशत से अधिक हो गई। गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय कंपनियों के प्रदर्शन पर भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि 2012-13 में उनके लाभ मार्जिन गिर गये। इसने संभवतः निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचतों को प्रभावित किया। 2013-14 में विनिर्माण क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि के चलते, निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत दर में पुनरुत्थान की संभावना नहीं है।

1.37 ऊपर वर्णित बृहत आर्थिक मापदंडों के रुझानों का अन्य मापदंडों अर्थात् मुद्रास्फीति, भुगतान शेष आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। इनकी चर्चा नीचे की गई है।

बचत दर 2007-08 से काफी कम हो गई है।

हालिया वर्षों में, परिवारों ने वित्तीय आस्तियों की तुलना में भौतिक आस्तियों में अधिक बचत करने की प्रवृत्ति दिखाई।

कीमतें और मौद्रिक प्रबंध

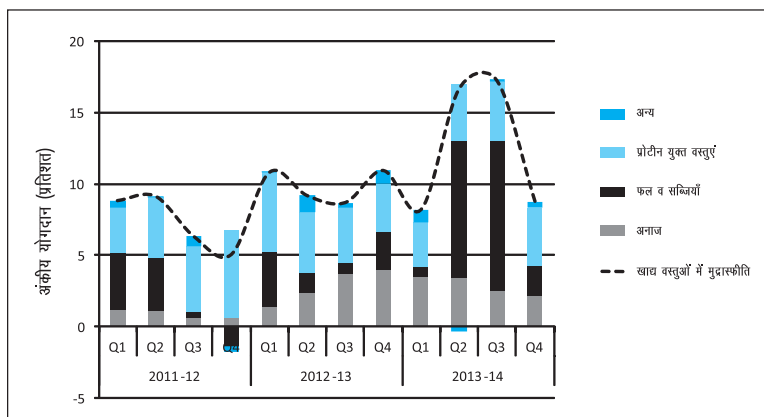
मुद्रास्फीति

1.38 औसत हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति कम होती हुई 2013-14 में लगभग 6 प्रतिशत के चार वर्षीय न्यूनतम स्तर तक आ गई। ऐसा इससे पहले के तीन वर्षों की 8.6 प्रतिशत की औसत के बाद हुआ। मुद्रास्फीति में यह गिरावट वैश्विक वस्तु मूल्यों में हुई कमी की पृष्ठभूमि में खाद्य भिन्न क्षेत्र में काफी कमी हो जाने के कारण हुई। तथापि, घरेलू खाद्य वस्तुओं से आने वाला दबाव उच्च बना रहा। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2013-14 की पहली तिमाही में 5 प्रतिशत से कम बनी रही। तथापि, सब्जियों और अनाजों की उच्चतर मुद्रास्फीति ने दूसरी और तीसरी तिमाही में तेजी लाई, जब हेडलाइन मुद्रास्फीति क्रमशः 6.6 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत हो गई। अनाज मुद्रास्फीति में कुछ सुधार और सब्जियों के मूल्यों में सुधार के साथ, हेडलाइन मुद्रास्फीति गिरकर 2013-14 की अंतिम तिमाही में 5.4 प्रतिशत रह गई। खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति (कोर मुद्रास्फीति) वर्षभर हल्की बनी रही और कम हो कर 2013-14 में चार वर्ष के सबसे कम स्तर 2.9 प्रतिशत पर पहुंच गई। इससे पता चलता है कि व्यापक-आधार वाली मुद्रास्फीति के अंतर्निहित दबाव कुछ कम हुए हैं।

1.39 नई श्रृंखला पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (संयुक्त) के अनुसार मुद्रास्फीति पिछले कुछ वर्षों में उच्चतर खाद्य मुद्रास्फीति के चलते 9-10 प्रतिशत के लगभग रहकर स्पष्टतः दृढ़ बनी रही। तथापि, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति ने दिसम्बर 2013 के बाद सामान्य होना शुरू किया तथा सब्जियों और अण्डे, मांस तथा मछली की मुद्रास्फीति में कमी का अनुसरण करते हुए कम होकर फरवरी 2014 में 25-माह के सबसे कम स्तर 8.0 प्रतिशत पर आ गई। दूसरी ओर, खाद्य और ईंधन (कोर) को छोड़कर, सीपीआई मुद्रास्फीति, सेवा प्रेरित घटकों जैसे चिकित्सा, शिक्षा, पारिवारिक अपेक्षाएं, आदि में उच्चतर मुद्रास्फीति के कारण अधिक बनी रही।

हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के प्रमुख योगदान-कारक

1.40 मुख्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति का स्तर और इसकी घट-बढ़ 2013-14 की अंतिम तिमाही तक आठ तिमाहियों के दौरान काफी विविध रही। 2013-14 में मुद्रास्फीति मुख्यतः खाद्य और ईंधन तक सीमित रही थी, जिसने सम्पूर्ण मुद्रास्फीति में लगभग दो-तिहाई का योगदान किया था। पिछले कुछ वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति, संरचनागत और मौसमी कारकों का परिणाम रही है। हालांकि खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति निरंतर बनी हुई है, जबकि इसके निर्धारक समय-समय पर बदल रहे हैं। उदाहरणार्थ, अनाज और प्रोटीन युक्त मदें 2013-14 की पहली तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति की प्रमुख योगदान कारक थीं, बल्कि सब्जियों, विशेषकर प्याज, ने दूसरी और तीसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति को उछाला



स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय डीआईपीपी

अर्थव्यवस्था की स्थिति

खाद्य मुद्रास्फीति खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति से कहीं अधिक रही है।

चित्र 1.4 : खाद्य मदों की मुद्रास्फीति के प्रधान कारण

(चित्र 1.4)। खाद्य समूह के भीतर, पण्य उप-समूहों, फल और सब्जियों तथा अण्डा, मांस, एवं मछली का योगदान अधिक रहा है। प्रोटीन-आधारित मदों जैसे अण्डा, मांस तथा मछली में व्याप्त मुद्रास्फीति बढ़ते आय स्तरों के कारण इन मदों की खपत के हिस्से में वृद्धि होने के कारण रही है।

1.41 खाद्य मुद्रास्फीति आंशिक रूप से वितरण चैनलों में मौजूद अदक्षता के चलते आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य वस्तुओं की अधिक बर्बादी के कारण होती है। राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियमों के उपबंधों ने पण्यों के वितरण में प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों के सृजन और कृषि पण्यों के लिए राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में रुकावट पैदा की है। खाद्य वस्तुओं के वितरण में मौजूद मध्यस्थता के कई स्तरों के कारण भी उपभोक्ता के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वितरण चैनलों और आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य बर्बादी कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। आधुनिक भाण्डागारों, शीतागार, रीफर वैन, वैज्ञानिक पैकेजिंग और उतराई-चढ़ाई सहित विपणन अवसंरचना में बड़े निवेश करने से वितरण चैनलों को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकारों को एपीएमसी अधिनियम में मौजूद अवरोधक उपबंधों को समाप्त करने और किसानों के लिए वैकल्पिक कारोबार के अवसरों का सकारात्मक ढंग से संवर्धन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी।

1.42 ईंधन मुद्रास्फीति विगत दूसरी और तीसरी तिमाहियों में दोहरे अंकों में बनी रही। ईंधन और विद्युत मदों में व्याप्त उच्च मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण कई राज्यों में बिजली के टैरिफों का यौक्तिकीकरण, डीजल मूल्यों के अधिक अंतरण (पास थ्रू) करने की अनुमति संबंधी नीति लागू करना और अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपये का अवमूल्यन होना था।

मुद्रास्फीति की संभावनाएं

1.43 आईएमएफ द्वारा किए गए पूर्वानुमानों में अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों के अनुकूल बने रहने की आशा की गई है। यह डब्ल्यूपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति को सामान्य करने में सहायक होना चाहिए। तथापि, प्रमुख खतरा एल-निनो प्रभाव के कारण 2014-15 के दौरान सामान्य से कम मानसून होने से और मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक स्थिति के कारण तेल के उच्चतर मूल्यों से पैदा होता है। उर्वरकों सहित कृषि की निविष्टियों पर सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में वृद्धि करने से संबंधित सरकार के निर्णयों का भी खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव हो सकता है।

मौद्रिक घटनाक्रम

1.44 क्रमिक मौद्रिक सुलभता में जो 2013-14 की शुरुआत में स्फीतिकारी दबावों में कुछ कमी के साथ आरंभ हुई थी, विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर करने की आवश्यकता के जरिए व्यवधान हुआ। मई 2013 में, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा नकदी की मात्रात्मक सुलभता में धीरे-धीरे कमी लाने के संकेत थे। इसके बाद पूंजी बहिर्वाहों में जो उछाल आया, उससे रुपये के मूल्य में तेजी से अवमूल्यन हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बहाल करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि की और घरेलू मुद्रा बाजार नकदी को संकुचित किया।

1.45 मध्य-जुलाई 2013 में किये गए उपायों में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर में 200 आधार बिन्दु (बीपीएस) का इजाफा करके उसे 10.25 प्रतिशत करना; दैनिक नकदी समायोजन निधि (एलएएफ) उधार को संबंधित बैंकों की निवल मांग और सावधि देनदारियों (एनडीटीएल) के 0.5 प्रतिशत तक सीमित करना; और न्यूनतम दैनिक नकदी आरक्षण अनुपात (सीआरआर) अपेक्षा को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत करना शामिल हैं। नकदी प्रबंध हुईयों की साप्ताहिक नीलामी भी नकदी उपलब्ध कराने के लिए आयोजित की गई थी।

इन उपायों ने मांग दर को एमएसएफ दर तक पहुंचा दिया जिससे एमएसएफ दर प्रभावी पॉलिसी दर बन गई।

1.46 विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता कम होने के पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 सितम्बर 2013 की अपनी मध्य-तिमाही समीक्षा के बाद से आपवादिक उपायों को चरणबद्ध तरीके से सामान्य रूप में लाने का कार्य शुरू किया। ब्याज दर की परिधि को सामान्य मौद्रिक नीतिगत प्रचालनों के समनुरूप बनाया गया। ऐसा करने के लिए 20 सितम्बर, 2013 और 29 अक्टूबर 2013 के बीच एमएसएफ दर को 3 चरणों में घटाकर 8.75 प्रतिशत किया गया तथा साथ ही रेपो दर को 2 चरणों में प्रत्येक बार 25 आधार बिन्दु बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत किया गया ताकि मुद्रास्फीति और स्फीतिकारी संभावनाओं पर काबू पाया जा सके। बैंकों द्वारा बनाये रखे जाने वाले न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष को अपेक्षित 99 प्रतिशत से घटाकर 95 प्रतिशत किया गया ताकि बैंकों को नकदी का बेहतर प्रबंधन करने में थोड़ी स्वतंत्रता मिल सके। नकदी वर्धन के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में और सावधि मुद्रा बाजार को विकसित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग व्यवस्था के एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत की समतुल्य राशि के 7 दिवसीय और 14 दिवसीय साप्ताहिक परिवर्तनीय दर वाले रेपो की शुरुआत की।

1.47 भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जनवरी, 2014 को मौद्रिक नीति की अपनी तीसरी तिमाही समीक्षा में मुद्रास्फीति बढ़ने के जोखिम के कारण रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि करके उसे 8 प्रतिशत पर ला दिया। इस उपाय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति कम करने के मार्ग पर सुरक्षित ढंग से ले जाना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जून, 2014 को अपने दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण में पॉलिसी रेपो दर को 8 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और सांविधिक नकदी अनुपात में 50 आधार बिंदुओं की कमी की, जिससे वह 23 प्रतिशत से कम होकर 22.5 प्रतिशत पर आ गई। इस प्रकार, आरबीआई बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे अपनी सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता कम करें ताकि वे निजी क्षेत्र को अधिक उधार देने में समर्थ हो सकें।

1.48 वर्ष 2013-14 के पूर्वार्ध में नकदी की तंगी की स्थितियां बनी रहीं जो विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर करने के नीतिगत उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती हैं। मुद्रा बाजार 2013-14 की पहली तिमाही के दौरान व्यवस्थित बने रहे जब मांग दर रिवर्स रेपो और एमएसएफ दरों द्वारा निर्धारित परिधि के बीच मंडराती रही और पॉलिसी (रेपो) दर के नजदीक रही। तथापि, जुलाई और अगस्त 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा दर में व्याप्त अस्थिरता पर काबू पाने के लिए किए गए आपवादिक उपायों ने मुद्रा बाजार पर असर डाला और बाद में इससे मुद्रा बाजार दरें परिधि से बाहर चली गईं।

मुद्रास्फीति पर काबू पाने एवं विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता लौटाने के लिए आरबीआई ने मौद्रिक नीति में सख्त रुख अपनाया।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान शेष और विदेशी ऋण

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

1.49 वैश्विक निर्यातों और आयातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2000 के क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत से बढ़ता हुआ वर्ष 2013 में क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत हो गया। भारत के कुल वस्तु व्यापार में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसका सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 2000-01 के 21.8 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 44.1 प्रतिशत हो गया।

1.50 भारत का वस्तु निर्यात 2013-14 में 312.6 बिलियन अमरीकी डॉलर (सीमा शुल्क आधार पर) तक जा पहुंचा। इसने पिछले वर्ष के दौरान की 1.8 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल-मई 2014 में, निर्यातों में 2013 की तदनु रूप अवधि की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरी सामान और रसायन तथा संबद्ध उत्पादों का निर्यात 2013-14 में कुल निर्यातों के आधे हिस्से से अधिक था। 2012-13 की तुलना में 2013-14 में आयातों

के मूल्य में 8.3 प्रतिशत की गिरावट हुई जिसकी वजह तेल-भिन्न आयातों में 12.8 प्रतिशत की गिरावट हुई। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) के आयातों के मूल्य में वर्ष 2013-14 में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के कारण सोने का आयात 2011-12 के 1078 टन से कम होकर 2012-13 में 1037 टन तथा और कम होकर 2013-14 में 664 टन रह गया। मूल्य के संदर्भ में, सोने और चांदी के आयात में 2013-14 में 40.1 प्रतिशत की गिरावट हुई और वह 33.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया। 2013-14 में आयातों में हुई जबरस्त गिरावट और साधारण निर्यात वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत का व्यापार घाटा 2012-13 के 190.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से कम होकर 137.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया जिससे कैंड में कमी आई।

सेवा व्यापार

1.51 सेवा निर्यातों में 2012-13 के 2.4 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालिया वर्षों में सेवा व्यापार में अधिशेष (निवल सेवाएं) भारत के बढ़ते वस्तु व्यापार घाटे को वित्तपोषित करने का मुख्य स्रोत रहा है। 2006-07 से 2012-13 के दौरान इस अधिशेष ने वस्तु व्यापार घाटे के औसतन लगभग 38 प्रतिशत हिस्से को वित्तपोषित किया। जहां 2012-13 में, निवल सेवाओं ने वस्तु व्यापार घाटे के 33.2 प्रतिशत को वित्तपोषित किया, वहीं 2013-14 में सेवा निर्यातों में हुई साधारण वृद्धि और उनके आयातों में हुई गिरावट के परिणामतः निवल सेवाओं ने वस्तु व्यापार घाटे के लगभग आधे हिस्से को वित्तपोषित किया।

भुगतान शेष

1.52 वर्ष 2013-14 में, विशेषकर अंतिम तीन तिमाहियों में भारत के भुगतान शेष की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यूरो क्षेत्र के संकट और कतिपय प्रमुख आयातों के लिए लोचहीन घरेलू मांग के परिणामस्वरूप 2011-12 के दौरान भुगतान शेष पर देखा गया दबाव 2012-13 और 2013-14 की पहली तिमाही में भी जारी रहा। 2012-13 में कैंड में भारी वृद्धि हुई और यह 88.2 बिलियन अमरीकी डॉलर (स.घ.उ. का 4.7 प्रतिशत) के रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचा तथा यह 2011-12 के 78.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से कहीं अधिक हो गया। 2011-12 और 2012-13 में खतरनाक रूप से अवहनीय स्तरों पर रहने के बाद, 2013-14 में भुगतान शेष की स्थिति में हुआ सुधार एक राहत जैसा है। तथापि, 2013-14 में सामने आए परिणाम मिलेजुले थे: पहली तिमाही में कैंड के ऊंचे स्तर जिसके बाद धीमा सुधार हुआ; मई 2013 तक पूंजी प्रवाहों के जरिए आम तौर पर पर्याप्त वित्तपोषण किया गया; जून-अगस्त 2013 में तेजी से सुधार जिसके बाद सितंबर-नवंबर 2013 में स्थिति में उछाल आया। जून-अगस्त 2013 में हुआ सुधार यूएस फेड द्वारा परिसंपत्तियों की खरीद को निश्चित रूप से कम किए जाने को लेकर बाजार में व्याप्त आशंका के कारण हुआ। उसके बाद प्रवाहों में आया उछाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवासी जमाराशियों और बैंकों के विदेशी उधार कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त विशेष अदलाबदली मार्ग (स्वॉप विंडो) के कारण हुआ।

1.53 2012-13 में कैंड की वृद्धि मुख्यतया कमजोर पड़ते निर्यातों और अपेक्षाकृत स्थिर आयातों से उत्पन्न व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के कारण हुई। स्थिर आयातों की वजह कच्चे पेट्रोलियम आयातों पर भारत की निर्भरता और वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत से ही बढ़ते स्वर्ण आयात हैं। हालांकि उच्च कैंड का वित्तपोषण पर्याप्त था और 2008 के संकट से पूर्व व्याप्त सामान्य प्रवृत्तियों की तर्ज पर था, लेकिन 2011-12 के दौरान और मई 2013 से व्याप्त अपर्याप्तता ने यह संकेत दिया कि कैंड की आरंभिक सीमा से परे, इसका वित्तपोषण एक समस्या खड़ी कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2008 के संकट के बाद की अवधि में, जोखिम लेने से अधिकाधिक बचने की प्रवृत्ति बनी हुई है, जिसके कारण पूंजी प्रवाहों और रुपये की विनिमय दर पर प्रभाव पड़ सकता है।

मांग में कमी एवं अनावश्यक आयातों पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप व्यापार घाटा कम हुआ एवं कैंड भी कम हुआ।

1.54 सरकार ने शीघ्रतापूर्वक किए गए इन उपायों के जरिए स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए – सोने जैसे अनावश्यक आयातों पर प्रतिबंध लगाना; सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में वृद्धि करके उसे 10 प्रतिशत की ऊंचाई पर लाया जाना, अर्ध-सरकारी बांडों के जरिए और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के उदारीकरण के जरिए पूंजी प्रवाहों में वृद्धि करने के उपाय करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (बैंक) और बैंकों के विदेशी उधारों के लिए विशेष अदलाबदली मार्ग (स्वॉप विंडो) भी स्थापित की जिससे 34 बिलियन अमरीकी डॉलर जुटाए गए। इन उपायों के परिणामस्वरूप, अगली तीन तिमाहियों में और 2013-14 के संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए भुगतान शेष की स्थिति में भारी बदलाव हुआ। अधिक निर्यातों और अपेक्षाकृत कम आयातों के चलते व्यापार घाटा 2012-13 के 10.5 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.9 प्रतिशत रह गया।

1.55 2013-14 में भुगतान शेष आधार पर व्यापार घाटे में हुई 48.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल गिरावट में से, सोने और चांदी के आयात में हुई कमी ने लगभग 47 प्रतिशत, पीओएल-भिन्न और स्वर्ण-भिन्न आयातों में हुई कमी ने 40 प्रतिशत और अधिक आयातों ने 25 प्रतिशत का योगदान किया। पीओएल के तहत अधिक आयातों और डीजीसीआईएंडएस (वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय)-भिन्न आयातों में हुई वृद्धि ने नकारात्मक रूप से इस कटौती में योगदान किया जो 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 12 प्रतिशत तक रही।

1.56 निवल अदृश्य अधिशेष प्रति तिमाही 28-29 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर स्थिर रहे जिनके परिणामस्वरूप 2013-14 में 115.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का समग्र निवल अधिशेष रहा। सॉफ्टवेयर सेवाओं में साधारण सुधार हुआ जो 2012-13 के 63.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से बढ़कर 2013-14 में 67.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। कारक भिन्न सेवाएं 2012-13 के 64.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 73.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गईं। ऐसा अंशतः कारोबारी सेवाओं के धनात्मक हो जाने के कारण हुआ जहां 2012-13 के 1.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के बहिर्वाह के मुकाबले 2013-14 में 1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवल अंतर्वाह हुआ। इस प्रकार कैंड 2012-13 के 88.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले कम होकर 2013-14 में 32.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। 2013-14 में कैंड सकल घरेलू उत्पादन का 1.7 प्रतिशत था 2008 के संकट-पूर्व स्तरों की तुलना में बेहतर है।

1.57 पूंजी प्रवाह (निवल) 2012-13 के 92.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से तेजी से कम होते हुए 2013-14 में 47.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गए। यह गिरावट मूलतः पोर्टफोलियो निवेश में कमी और “अल्पावधिक ऋण” तथा “अन्य पूंजी” के निवल बहिर्वाह को प्रतिबिंबित करती है। तथापि, अंशतः घरेलू और अंशतः विदेशी कारकों के कारण तिमाहियों में भी बड़ी घट-बढ़ हुई। विशेष स्वाप विंडो के जरिए पूंजी अंतर्वाहों में वृद्धि करने के उपाय के परिणामस्वरूप लगभग 34 बिलियन अमरीकी डॉलर के भारी अंतर्वाह प्राप्त हुए।

1.58 इन अंतर्वाहों के साथ-साथ कैंड के अपेक्षाकृत कम स्तरों के चलते 2013-14 में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। मार्च 2013 के 292.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले मार्च 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 304.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर था। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा भंडार में मार्च 2014 में भुगतान शेष आधार पर 15.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की भंडार वृद्धि के मुकाबले मामूली अंकों में 12.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई। इस अंतर की वजह विभिन्न मुद्राओं में हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण अमरीकी डॉलर से इतर मुद्राओं में धारित परिसंपत्तियों में हुई मूल्यांकन हानि और सोने की कीमतों में हुई गिरावट है। 20 जून, 2014 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 314.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

2013-14 में पूंजी प्रवाह साधारण रहे, परन्तु विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया।

1.59 2013-14 में मई 2013 में रुपये के मूल्य में गिरावट शुरू हो गई। यह मूल्यहास जून और अगस्त 2013 में अधिक उजागर हुआ जो माह दर माह आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक था। सितंबर 2013 में मुद्रा दर प्रति अमरीकी डॉलर गिरकर 63.75 रुपये के स्तर पर आ गई। उसके बाद, कैड कम करने और पूंजी प्रवाहों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2013 में रुपया वापस प्रति अमरीकी डॉलर 61.62 रुपये के औसत स्तर पर आ गया। तदनंतर रुपया एक परिधि में ही रहा और 2013-14 में स्थिर रहा। इस प्रकार 2014-15 में अब तक मुद्रा दर 2013-14 के उत्तरार्ध में देखे गए पैटर्न को प्रतिबिंबित करती है जब विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) प्रवाहों में उछाल से विदेशी मुद्रा और इक्विटी बाजारों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा था; लेकिन इक्विटी सूचकांकों में वृद्धि के मुकाबले रुपए की मूल्य वृद्धि सीमित ही रही है।

विदेशी ऋण

1.60 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकबारगी जमा राशि जुटाने से भारत के विदेशी ऋण पर असर पड़ा। भारत का विदेशी ऋण स्टॉक मार्च 2012 के 360.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले मार्च 2013 में 404.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था। दिसम्बर, 2013 के अंत तक यह बढ़कर 426.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। भारत के विदेशी ऋण में अधिकांशतः दीर्घावधिक ऋण शामिल हैं और ये नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर ही रहे हैं जिसका कारण व्यापक हित ग्राही समीकरणों को देखते हुए, विशिष्ट पूंजीगत अन्तर्वाहों के विविध ऋण पर लगाए गए विवेकपूर्ण प्रतिबंध हैं।

विकास की बहाली हेतु प्राथमिकताएं

1.61 दोनों घाटे काफी हद तक नियंत्रणीय सीमा में रहने के चलते, मन्द विकास और स्फीतिकारी दबावों के बृहद आर्थिक परिणामों पर तत्काल ध्यान दिया जाना जरूरी है। अल्पकालिक स्थिरीकरण के उपायों के अलावा, नीतिगत स्तर पर व्यापक श्रृंखलाबद्ध संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिससे कि आपूर्ति पक्ष के दबावों को हल्का किया जा सके और मांग को बढ़ाने के लिए क्षेत्र सम्बन्धित प्रोत्साहन दिए जा सकें। विकास को बहाल करने की दृष्टि से कतिपय विशिष्ट प्राथमिकताएं इस प्रकार तय की गई हैं।

- विकास दर को बनाए रखने के लिए निवेश की बहाली बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए परियोजनाओं की स्वीकृति में तेजी तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ-साथ क्षेत्र-वार विशिष्ट निवेश प्रोत्साहन नीतियों का होना अत्यन्त आवश्यक है।
- मध्यम आवधिक संदर्भों में देखें तो अनवरत उच्चतर विकास के लिए उत्पादकता बढ़ाने वाले संरचनागत सुधारों का होना बहुत जरूरी है।
- निवेश बहाली के प्रयासों से जुड़ी वे नीतियां हैं जो विनिर्माण क्षेत्र के लिए जरूरी है जिसके कि महत्वपूर्ण विपणन और विनिर्माण प्रभाव होते हैं। कराधान नीतियों व प्रशासन को सहज और सरल बनाना, ऐसे बोझिल कानूनों का निरसन जोकि बाजार पहुंच को बाधित करते हैं, फर्मों में प्रवेश/निकास तथा उनका विस्तार, वाणिज्यिक विवादों के लिए विवाद निपटान के कार्यवाही तंत्र का नवीकरण करना आदि वे प्रमुख उपाय हैं जिनके कारण नीतियों में निश्चितता का महत्वपूर्ण घटक लाया जा सकता है। नीतिगत सुनिश्चितता अनवरतता और पारदर्शिता के माहौल से आगे चल कर कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा।
- बृहद आर्थिक स्थिरता का सुदृढीकरण जो स्थिर एवं तीव्रतर विकास का मूलाधार है, राजकोषीय अनुशासन, नियंत्रणीय चालू खाता शेष और मूल्य स्थिरता पर टिका है। इन नीतिगत चुनौतियों में ये शामिल हैं:
 - पूंजीगत व्यय में कोई समझौता किए बगैर राजकोषीय घाटे पर काबू बनाए रखना;

विकास पुनरुद्धार की प्राथमिकताओं में ये शामिल हैं: निवेश पुनरुद्धार, बृहद आर्थिक स्थिरता का सुदृढीकरण, गैर-कृषि रोजगारों का सृजन, अवसंरचना का सुदृढीकरण और कृषि विकास को बढ़ावा देना।

- कैंड को सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 2-2.5 प्रतिशत के बीच रखना। यह भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यदि विकास-बहाली होने पर तेल-भिन्न आयात बढ़ जाएं और तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाए। इसलिए इससे सतत निर्यात विकास में सहायक नीतियां अपनाना प्रासंगिक होगा।
- मुद्रास्फीति घटाने के प्रयासों को और तीव्र और त्वरित किया जाना ताकि न सिर्फ प्रत्यक्ष तौर पर दिखने वाले बृहत आर्थिक परिणामों का मुकाबला किया जा सके बल्कि बाहरी चुनौतियों का ज्यादा प्रभावी ढंग से सामना करने में एक मौद्रिक गुंजाइश बनाए रखने के लिए आर.बी.आई. को समर्थ बनाया जा सके।
- मानव-आबादी के लाभ लेने हेतु गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना होगा। चूंकि कृषि क्षेत्र अभी भी काफी तादाद में लोगों को रोजगार दे रहा है, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, विनिर्माण तथा श्रम-प्रधान अन्य सेवा क्षेत्रों पर नीतिगत ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
- शहरी तथा ग्रामीण संदर्भ में भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना जो सुदृढ़ विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और तालमेल बैठा सकते हैं, आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने और उन्हें दुबारा हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है।
- कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर स्थिर विकास के चलते सतत आर्थिक विकास संभव है। इसके लिए इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता, कृषि संरक्षण और बीमा की जरूरत है और साथ ही प्रापण, विपणन, परिवहन, भण्डारण तथा प्रसंस्करण की नीतियों पर नए सिरे से विचार किए जाने की महती आवश्यकता है।

2014-15 के लिए संभावनाएं

1.62 5 प्रतिशत से कम विकास के मौजूदा दौर में आगमन बड़ी तेजी से हुआ। परियोजना क्रियान्वयन में विलम्ब, मंद घरेलू भावनाओं और कतिपय अनिश्चित ग्लोबल परिदृश्य के साथ-साथ अवसंरचनात्मक बाध्यताओं ने सामान्य मंदी में योगदान दिया जिसके साथ-साथ वृहद आर्थिक स्थिरीकरण विशेषकर चुनौतीपूर्ण हो गया है। इन कारकों के चलते जोखिम से बचने की प्रवृत्ति आई तथा निवेश गतिविधियों में काफी अनिश्चितता बढ़ी। चालू वृहद आर्थिक स्थिति राजकोषीय उत्प्रेरण को रोकती है। इसी प्रकार, विकास को बहाल करने की दृष्टि से मौद्रिक नीतिगत आकलनों और परिकलन का काम भी निरन्तर जारी मुद्रास्फीति के कारण दूभर हो गया है और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय परिस्थितियों में व्याप्त अनिश्चितता और अभी हाल में रुपए के मूल्य में हुई गिरावट के कारण और भी पेचीदा हो गया है। सरकार और आर.बी.आई. द्वारा किए गए लक्षित उपायों से विदेशी आर्थिक स्थितियां महत्वपूर्ण स्तर तक सुधरीं, भले ही भारत निवेशकर्ताओं के संवेगों के और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत परिवर्तनों के प्रति जोखिम ग्रस्त रहा। विकास प्रक्रिया की गति बहाल करने के लिए घरेलू स्तर पर वृहद-आर्थिक सन्तुलन और दक्षता कौशल को बढ़ाए जाने की जरूरत होती है। इसके लिए इस दिशा में नीतियां निर्धारित करते समय राजकोषीय समेकन पर अडिग रहना और अवसंरचनात्मक बाधाओं को पार किया जाना जरूरी है। यद्यपि इस दिशा में कई उपाय किए गए हैं, लगभग 7-8 प्रतिशत पर विकास दर को हासिल करना इस वर्ष और अगले वित्त वर्ष के बाद ही संभव हो सकेगा।

1.63 2014-15 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कुछ सुधार होने पर ग्लोबल आर्थिक गतिविधियों के कुछ मजबूत होने की उम्मीद है। यूरोपीय क्षेत्र में वर्ष 2012 और 2013 (आई.एम.एफ., डब्ल्यू.ई.ओ. अप्रैल, 2014) में देखे गए संकुचन के मुकाबले 1 प्रतिशत के उपर की विकास दर दर्ज करने की संभावना है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीतिगत उपाय, नकारात्मक निक्षेप सुविधा ब्याजदर की

संरचनागत रूकावटों को दूर करने के लिए किये गए कुछ उपायों के बावजूद, लगभग 7-8 प्रतिशत की विकास दर को हासिल करना इस वर्ष और अगले वित्त वर्ष के बाद ही संभव होगा।

शुरूआत करने से आर्थिक गतिविधियों का बढ़ना संभावित है। इसके अतिरिक्त, अमरीका में रीयल क्षेत्र में निष्पादन (जो कि कालान्तर में कम होना संभावित है) प्रमुख कारक है जोकि वर्ष 2014-15 में वैश्विक आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, विकासशील एशियाई देशों में विकास की संभावना सामान्यतया लाभकर है जहां मुद्रास्फीति, अवसंरचनात्मक गत्यावरोधों और बाहरी असन्तुलों से जूझना होगा। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मंदी एक अहम मुकाम पर पहुंच गई है।

1.64 बढ़ी हुई अस्थिरता के साथ-साथ गिरावट की स्थिति, जो कि मिसाल के तौर पर, भारत में 2008-09 के बाद नियत निवेश में देखी गई, अक्सर ऐसे आघातों (उदाहरणतः सामान्य से कम मॉनसून और/अथवा तेल की कीमतों में वृद्धि) के अंतरण चैनलों और प्रभावों को अधिक पैना कर देती है तथा सकारात्मक माहौल बनाने में बाधा खड़ी करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर स.घ.उ. में केवल क्रमिक पुनरुद्धार कर सकती है जो 2014-15 में 5.4-5.9 प्रतिशत के बीच में होना अनुमानित है। इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल 2014 में औद्योगिक क्षेत्र में देखी गई विकास बहाली को वर्ष की शेष अवधि में भी जारी रहेगी और सामान्य तौर पर तेल कीमतों के सकारात्मक परिदृश्य बने रहेंगे (मध्यपूर्व एशिया में हालिया घटनाक्रमों में व्याप्त अनिश्चितता के बावजूद) और इन सुस्पष्ट अस्थिरवादी आघातों (इसमें औसत से कम स्तर का मानसून भी शामिल है) के न रहने की प्रत्याशा की गई है। उपर्युक्त श्रेणी में विकास एक तीव्र गति को दर्शाता है, जिसे सुस्थिर चालू खाते में के साथ बेहतर बाहरी आर्थिक स्थितियों, धीमे पूंजी अंतवाहों, सुधरी हुई राजकोषीय स्थितियों तथा दूसरी तरफ आपूर्ति के क्षेत्र में बेहतर तथा प्रचुर विद्युत उत्पादन और विनिर्माण और कतिपय गैर सरकारी क्षेत्र में सेवाओं में हुए सुधार से मदद मिलेगी।

1.65 2014-15 में निम्नलिखित कारणों से विकास दर के उपर्युक्त श्रेणी में कमोवेश बने रहने का अनुमान है:- (i) निवेश चक्र को गतिशील बनाने के लिए शुरू किए गए उपायों (जिनमें परियोजना मंजूरी और उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन शामिल हैं) का असर केवल धीरे-धीरे हो रहा है; (ii) कतिपय एशियाई अर्थव्यवस्थाओं खासकर चीन में सकारात्मक विकास; (iii) मुद्रास्फीति का अभी भी बढ़ा हुआ स्तर नीतिगत दरों को कम करने के लिए आर.बी.आई. के कार्यक्षेत्र को बाधित कर रहा है; और (iv) औसत से कम स्तर का मानसून होने की संभावना। भू-राजनैतिक तनावों के अधिक लंबे समय तक चलने के कारण भी जोखिम उभरा है। सकारात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें तो विशाल परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन के लिए संस्थागत सुधार और प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उम्मीद से कहीं ज्यादा सुदृढ़ सुधार जैसे कारकों से भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंची दरों पर विकास हासिल करने में सहायता मिल सकती है।

क्षेत्रक विकास

1.66 आगे मुख्य क्षेत्रक मुद्दों और घटनाक्रम की रूपरेखा दी गई है। ये घटनाक्रम उस बृहत आर्थिक परिदृश्य का हिस्सा हैं जो पिछले खण्डों में बताया गया है।

कृषि एवं खाद्य प्रबन्धन

1.67 पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में खासी तरक्की की गई है। 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न के अंतर्गत समग्र क्षेत्रीय कवरेज में लगभग 40 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2013-14 में 264.40 मिलियन टन खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना है जो कि पिछले पांच वर्षों के दौरान के औसत उत्पादन की तुलना

विनिर्माण में हुए बेहतर निष्पादन, भुगतान शेष की बेहतर स्थिति और सामान्य वैश्विक विकास पुनरुद्धार से 2014-15 में, अर्थव्यवस्था में 5.4-5.9 प्रतिशत की दर पर विकास होने की संभावना है।

वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन देखा गया।

में 20 मिलियन टन की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2012-13 में बागवानी उत्पादों के 265 मिलियन टन रहने का अनुमान किया गया है और ये पहली बार खाद्यान्नों तथा तिलहन के उत्पादन से अधिक बढ़ गए हैं।

1.68 कृषि तथा इससे सम्बद्ध दूसरे क्षेत्रों में भारी उत्पादन की वजह इस क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में हुई सुस्थिर वृद्धि रही है जो इस क्षेत्र में (निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2006-07 के 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 21.2 प्रतिशत (2004-05 के मूल्यों पर) हो गया। तथापि, कृषि तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में कुल जी.सी.एफ. में सार्वजनिक व्यय की सहभागिता (जिसमें सार्वजनिक निवेश और इनपुट सब्सिडी शामिल हैं) 2006-07 के 25 प्रतिशत से कम होती हुई 2013-14 में 14.7 प्रतिशत रह गई है। कृषि अनुषंगी स.घ.उ. के अनुपात के रूप में निजी निवेश 2007-08 के 12.6 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 18.1 प्रतिशत हो गया है।

1.69 2014-15 के मानसून में एल निनो के संभावित आगमन जैसी चिन्ताएं बरकरार हैं, जब प्रशान्त महासागर का सतहगत तापमान कई महीनों के लिए औसत से अधिक बढ़ जाता है तथा इसके कारण कई इलाकों में मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस घटना का भारत की कृषि और आगे चलकर खाद्यान्न मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुल खाद्यान्न और तिलहन का करीब 60 फीसदी हिस्सा खरीफ फसलों में उत्पादित होने के कारण और कृषि योग्य खेती में केवल 35 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित होने के चलते, भारतीय कृषि अभी भी काफी हद तक वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितम्बर) भारत में होने वाली कुल वर्षा में से लगभग 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी अदा करता है। जून 2014 में मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक सब-नार्मल/डेफीशिअंट दक्षिण-पश्चिम मानसून की संभाव्यता 71 प्रतिशत है तथा एल-निनो की संभावना 70 प्रतिशत है। तथापि, एल निनो का असर वर्ष के आकाशीय और अस्थायी सवितरण पर निर्भर होगा। पिछले पांच वर्षों के दौरान 11 जून तक मौसम विभाग के 36 उप-मंडल कार्यालयों और जिलों में वर्षा वितरण का तुलनात्मक अध्ययन इस वर्ष बेहतर वर्षा वितरण की संभावना व्यक्त करता है। तथापि, जलाशयों की भण्डारण स्थिति भी पिछले वर्ष और पिछले दस वर्षों के औसत से बेहतर है।

1.70 अन्य बातों के साथ-साथ, चुनिंदा कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में विस्तार के कारण खाद्यान्न उत्पादन में इज़ाफा हुआ है। सरकारी खरीद में काफी वृद्धि हो जाने के कारण केन्द्रीय पूल में 01 जून 2014 को विद्यमान स्थिति के अनुसार 77.7 मिलियन टन अनाज का बड़ा भंडार मौजूद है। खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति निवल उपलब्धता जो कि 2009 में 162.1 कि.ग्रा. वार्षिक थी बढ़कर 2013 में 186.5 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष हो गई है। इसी प्रकार, खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता भी 12.7 कि.ग्रा. वार्षिक से बढ़कर 15.8 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष हो गई है।

1.71 हालांकि ये उत्पादन अनुमान भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रचुरता के संकेत दे रहे हैं, तथापि, कतिपय चिन्ताएं भी बनी हुई हैं। भारतीय कृषि में उत्पादकता का स्तर ग्लोबल मानकों से अभी भी काफी कम है। 1980 के दशक के बाद से चावल और गेहूँ के उत्पादन स्तर में काफी अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि कपास की फसल ने पिछले दशक में आश्चर्यजनक रूप से उछाल भरी है, ऐसा मुख्यतः बी.टी. काँटन के कारण हुआ है; दालों तथा मोटे अनाज में भी थोड़ी वृद्धि देखी गई है। नई प्रौद्योगिकी और स्तरीय मशीनों, उपकरण आदि अवदानों के बिना वांछित उत्पादन स्तर को हासिल करना मुश्किल है। उर्वरकों के प्रयोग के घटते स्तर के कारण मिट्टी का अवक्रमण और जलस्तर में हो रही खतरनाक कमी खासकर पंजाब तथा हरियाणा में जहां के फसल के तौर-तरीकों में ऐसा होता है, आदि अन्य प्रमुख चिन्ताएं हैं। पोषाहार आधारित सब्सिडी नीति, जिसके क्षेत्राधिकार में यूरिया नहीं है, की नए सिरे से समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

1980 के दशक के बाद चावल और गेहूँ के उत्पादकता स्तरों में खास वृद्धि नहीं हुई है।

1.72 सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की कीमतों के कारण उर्वरकों के उपयोग में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सब्सिडी के सीधे अन्तरण पर गठित कार्यदल ने किसानों को उर्वरक सब्सिडी चरणबद्ध रूप से सीधे अदा किए जाने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों पर विचार किए जाने की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा में फसल विविधीकरण की स्कीम लागू की गई है और इससे आशा है कि तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा तथा किसान फसल विकल्पों को चुनने के लिए प्रोत्साहित होंगे। भारतीय कृषि में सीमित मात्रा में पूंजी की उपलब्धता वाले छोटे और सीमान्त कृषि क्षेत्रों की बहुलता ही भारतीय कृषि के यात्रिकीकरण में एक भारी बाधा बनी हुई है।

1.73 कृषि जिनसे के देशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दिया जाना जरूरी है। बाजार संबंधी उपादानों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली दखलअन्दाजियां वास्तव में व्यापार में बाधाएं ही खड़ी करती हैं। जरूरत इस बात की है कि कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय सामान्य बाजार विकसित किया जाए, जहां घरेलू बाजार में एक समान कर हों तथा कृषि उत्पादों के लिए एक दीर्घ-आवधिक सुस्थिर व्यापार नीति को प्रोत्साहन दिया जाए।

1.74 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) हेतु 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से खाद्यान्न खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को सभी राज्यों में लागू किए जाने की जरूरत है। इससे परिवहन की लागत, पारगमन सम्बन्धी नुकसान तथा अन्य हानियों से बचा जा सकेगा, इससे खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ेगी, खुले बाजार में खाद्यान्न की कीमतों में कमी और इस प्रकार खाद्यान्न सब्सिडी भी घटेगी।

उद्योग और अवसंरचना

1.75 सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उद्योग क्षेत्र ने 2012-13 में 1.0 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की थी जोकि कम होकर अब 2013-14 में 0.4 प्रतिशत रह गई है। इस खराब प्रदर्शन की मुख्य वजह खनन में संकुचन और विनिर्माण क्षेत्र में अवमन्दन का होना है। 2013-14 में विनिर्माण और खनन क्षेत्र सम्बन्धी स.घ.उ. में क्रमशः 0.7 प्रतिशत तथा 1.4 प्रतिशत की कमी हुई है। इसके निहित कारणों के मूल में निवेश विशेषकर 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के निवेश में आई बड़ी मंदी रही है।

1.76 आईआईपी आंकड़ों के अनुसार, खनन उत्पादन 2013-14 में लगातार तीन वर्ष से कम होता रहा तथा इसमें 0.6 प्रतिशत की गिरावट हुई। के.जी.-6 बेसिन से उत्पादन घटने के कारण प्राकृतिक गैस का उत्पादन बहुत गिर गया है। पिछले वर्ष के 4.0 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में विद्युत उत्पादन में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो हालिया वर्षों में क्षमता निर्माण में वृद्धि के कारण संभव हो सका है।

1.77 निर्माण क्षेत्र में व्याप्त मंदी के कारण इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में क्षमता से कम उपयोग हुआ है। 2013-14 में इस्पात तथा सीमेंट उपभोग के स्तर में क्रमशः 0.6 तथा 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में सबसे कमजोर निष्पादकों में से एक क्षेत्र रहा है। इसके सूचकांक में 2012-13 में 6.0 प्रतिशत की गिरावट हुई तथा और 2013-14 में 3.6 प्रतिशत की गिरावट हुई।

1.78 आठ प्रमुख उद्योगों यथा- कोयला, उर्वरक, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात और सीमेंट में औसत विकास दर 2012-13 के दौरान के 6.5 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 2.7 प्रतिशत रह गई। विकास में यह गिरावट मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल में संकुचन तथा कोयले, उर्वरक और रिफाइनरी उत्पादों के मंद विकास के कारण रही है।

खनन उत्पादन 2013-14 में लगातार तीसरे वर्ष भी कम रहा।

1.79 लगातार चल रही मंदी ने कारपोरेट क्षेत्र के निष्पादन को भी प्रभावित किया है। बिक्री वृद्धि विशेष रूप से सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि 2011-12 के पहली तिमाही के 24.9 प्रतिशत से कम होती हुई 2013-14 की तीसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत पर सिमट गई। 2013-14 की तीसरी तिमाही में क्षमता उपयोगिता (सी.यू.) व्यापक रूप से समान रही। 2013-14 में दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में तैयार वस्तुओं की सूची के बिक्री अनुपात में भी गिरावट देखी गई।

1.80 1000 करोड़ रुपए या इससे अधिक की लागत वाली कुल 239 केन्द्रीय अवसंरचना परियोजनाओं में से 99 नवीनतम सूची के संदर्भ में विलंबित बताई गई हैं और 11 परियोजनाओं के बारे में अर्थात् पिछले महीनों में कार्य समापन की तिथि (फरवरी, 2014 की फ्लैश रिपोर्ट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के संदर्भ में अतिरिक्त विलंब की सूचना दी गई है। अतिरिक्त विलम्ब की यह अवधि 1 से 26 महीनों की हो सकती है। ये सभी परियोजनाएं पेट्रोलियम, विद्युत, इस्पात तथा कोयला क्षेत्रों से संबंधित हैं।

1.81 अवसंरचनात्मक सेवाओं में, रेलों द्वारा ढोए गए माल, प्रमुख पत्तनों द्वारा और नागर विमानन क्षेत्र द्वारा निष्पादित (कार्गो आयात के सिवाय) 2013-14 के दौरान तुलनात्मक रूप से ज्यादा वृद्धि हुई है। सड़क क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 2013-14 के दौरान 33 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज कराई है, जबकि 2012-13 में यह वृद्धि 26.5 प्रतिशत रही थी।

1.82 उद्योगों में लगाया गया सकल बैंक ऋण के अन्तर्वाहों में 2012-13 के 17.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 14.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। खनन क्षेत्रों में दिया गया ऋण अन्तर्वाह 2013-14 के दौरान 0.05 प्रतिशत की दर पर स्थिर बना रहा। 2013-14 के दौरान विद्युत क्षेत्र के निष्पादन के मद्देनजर दिए गए ऋण प्रवाह में 24.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोलियम, रसायन और रासायनिक उत्पादों, मूल धातुएं, परिवहन और सभी इंजीनियरिंग क्षेत्रों ने विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में कमतर विकास दर दर्शाई है। प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में बैंक ऋण की वृद्धि की दर का औसत जो 2011-12 में 44.8 प्रतिशत था, घटकर 2013-14 में 17.7 प्रतिशत पर सीमित हो गया। दूरसंचार क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में निरन्तर गिरावट देखी गई है।

1.83 प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह (एफडीआई) ने 2012-13 में 60.9 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2013-14 में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई है। हाल के वर्षों में सेवाओं, निर्माण, दूरसंचार, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, औषधि तथा भेषज, ऑटोमोबाइल उद्योग, विद्युत, धातु उद्योगों तथा होटल और पर्यटन क्षेत्रों ने अधिकतम एफडीआई प्रवाहों को आकृष्ट किया है।

सेवा क्षेत्र

1.84 2001 से 2012 की अवधि के दौरान भारत का सेवा क्षेत्र 9 प्रतिशत की सी. ए.जी.आर. के साथ अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता तथा शेष दुनिया में दूसरे नम्बर पर सबसे तेज उभरते क्षेत्र के रूप से सामने आया है। 10.9 प्रतिशत सी.ए.जी. आर. के साथ चीन विश्व में पहले नम्बर पर है। विदेशी मुद्रा जुटाने, निर्यात वृद्धि और रोजगार मुहैया कराने में सेवा क्षेत्र का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। रोजगार सृजन में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 1993-94 के 19.7 प्रतिशत थी जोकि बढ़कर 2011-12 में 26.9 प्रतिशत हो गई है।

1.85 उद्योगों की तरह, सेवा क्षेत्र भी पिछले दो वर्षों के दौरान धीमे विकास का शिकार रहा है। विकास में यह मंदी व्यापार, होटलों तथा रेस्टोरेंट और परिवहन,

उद्योग में मंदी कारपोरेट क्षेत्र में व्याप्त कमतर बिक्री-वृद्धि में प्रतिबिम्बित हुई।

2013-14 में उद्योग को प्राप्त ऋण प्रवाह की वृद्धि कम रही।

भण्डारण और संचार की संयुक्त श्रेणी में तेज रही थी। तथापि, वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा तथा कारोबारी सेवा के क्षेत्रों में काफी विकास जारी रहा।

वित्तीय मध्यस्थता

1.86 एक सुदृढ़ बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उभरने के लिए वित्तीय सुधार बेहद जरूरी हैं। एक कार्यदक्ष वित्तीय तंत्र विकास, वित्तीय समावेशन और स्थिरता को बढ़ावा देगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम का पारित होना, वस्तुओं के वायदा व्यापार के विनियामक पर्यवेक्षण को वित्त मंत्रालय के तहत लाना और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण 2013-14 के प्रमुख घटनाक्रम हैं।

1.87 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र जिसमें वैश्विक वित्तीय संकट के ठीक बाद पर्याप्त समुत्थानशीलता दिखाई दी, पर पिछले दो वर्षों के दौरान वैश्विक और घरेलू आर्थिक मंदी के कारण असर पड़ा है। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की परिसम्पत्तियों की गिरती गुणवत्ता चिंता का एक बड़ा सबब रही है, जब बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में तेजी से बढ़ोत्तरी हो गई। बैंकिंग क्षेत्र का सकल एनपीए मार्च, 2011 में दिए गए कुल ऋण के 2.36 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2014 में कुल ऋण का 3.90 प्रतिशत हो गया (अनंतिम)। इस मंदी के फलस्वरूप और ऋण-निवेश के उच्च अनुपात के चलते कुछ उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों नामतः वस्त्र उद्योग, रसायन, लोहा और इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और दूरसंचार के एनपीए में तेजी से वृद्धि देखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (2013) में पांच क्षेत्रों-अवसंरचना, लोहा और इस्पात, वस्त्र उद्योग, विमानन और खनन-की दबावग्रस्त क्षेत्र के रूप में पहचान की है। सरकारी क्षेत्र के बैंक भी आम तौर पर 'उद्योग' क्षेत्र के प्रति और विशेष रूप से ऐसे दबावग्रस्त क्षेत्रों के प्रति जोखिमग्रस्त हैं।

1.88 नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है, 1 जनवरी, 2004 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। यह भारतीय पेंशन व्यवस्था में एक बड़े सुधार के रूप में है और इसमें व्यक्तिगत खाते, सुस्पष्ट अंशदान प्रणाली अपनाकर भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए एक स्थायी समाधान की बुनियाद रखी गई है। 7 मई, 2014 तक एनपीएस के तहत 67.41 लाख सदस्य नामांकित किए गए हैं और इसकी संचित निधि 51,147 करोड़ ₹ है। 1 मई, 2009 से एनपीएस को भारत में सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया था जिसमें वे स्वैच्छिक आधार पर शामिल हो सकते हैं। वर्ष 2010 में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों के लिए शुरू की गई स्वावलम्बन योजना जो आरंभ में 2010-11 में पंजीकरण करवाने वाले लाभार्थियों के लिए तीन वर्ष के लिए शुरू की गई थी, को अब 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में नामांकित लाभार्थियों के लिए पांच वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह इस योजना के तहत अंशदान के लाभ 2016-17 तक मिलते रहेंगे।

1.89 वित्तीय क्षेत्र को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिए उसमें सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने 24 मार्च, 2011 को एफएसएलआरसी गठित किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में संस्थागत, कानूनी और विनियामक फ्रेमवर्क तथा प्रचालनात्मक परिवर्तनों पर विधायी और गैर-विधायी दोनों प्रकार की विस्तृत सिफारिशों की हैं। एफएसएलआरसी द्वारा प्रस्तावित भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी) के मसौदे में ऐसे उपबंध हैं जो अधिकांश मौजूदा वित्तीय कानूनों का स्थान लेंगे। एफएसएलआरसी ने एक संशोधित वित्तीय विनियामक संरचना तैयार की है जो प्रत्येक संगठन के लिए स्पष्ट उद्देश्य निहित करके और यह हितों के टकराव से बचते हुए जवाबदेही बढ़ाएगी। इस परिवर्तित व्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकार के लिए संबंधित कार्यकलापों के लिए किफायत बरतना भी सुसाध्य होने की व्यवस्था की गई है।

1.90 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की 24 अक्टूबर, 2013 को हुई आठवीं बैठक में परिषद ने निर्णय लिया कि विनियामक स्वैच्छिक रूप से अभिशासन वर्धन वाली ऐसी सिफारिशों को अपनाएंगे जिनके लिए विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। इस कदम के परिणामस्वरूप, प्रारूप भारतीय वित्तीय संहिता के अभिशासन वर्धन के गैर विधायी पहलुओं को स्वेच्छा से अपनाने के संबंध में एक पुस्तिका निकाली गई है और एक एमआईएस विवरण तैयार किया गया है जो इसके अनुपालन पर नजर रखेगा।

1.91 आईएफसी को कार्यान्वित करने के लिए अनेक नए संगठनों की स्थापना की जरूरत पड़ेगी। एफएसडीसी ने चार नए संगठनों के संस्थागत निर्माण की शुरुआत करने का निर्णय लिया: समाधान निगम (आरसी) जो दबावग्रस्त वित्तीय फर्मों का पता लगाएगा और उनसे संबंधित कार्य करेगा; सरकारी ऋण प्रबंधन एजेंसी जो सरकार के लिए घरेलू और विदेशी उधार की प्रबंध व्यवस्था करेगी; वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण जो वित्तीय एजेंसियों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा; और वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केन्द्र जो एफएसडीसी के भीतर ही डाटाबेस का कार्य करेगा। इनसे भारतीय वित्तीय तंत्र का एक समग्र चित्र उभरेगा।

मानव विकास

1.92 बड़ी और युवा आबादी वाले भारत को मानव-आबादी की एक महत्तर स्थिति प्राप्त है। यहां कार्यक्षम आबादी का अनुपात 2001 में 58 था जोकि अनुमानतः अब बढ़कर 2021 तक 64 प्रतिशत पर पहुंचने वाला है। हालांकि इससे नए अवसर तो मिलते हैं लेकिन यह कई चुनौतियां भी खड़ी करती है। नीति नियामकों को देश की विकास परक नीतियां इस तरह से बनानी होंगी जोकि प्रचुरतः विद्यमान युवा आबादी पर लक्षित हों। मानव आबादी के लाभ हमें हमेशा नहीं मिलेंगे। अतः देश की आबादी को स्वस्थ, शिक्षित और पर्याप्त तौर पर कुशल बनाने के लिए समय रहते कुछ पूर्वोपाय कर लेने चाहिए।

1.93 संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट (एच.डी.आर. 2013) के अनुसार, भारत का मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) 2012 में 0.554 था जोकि 2012 की एच.डी.आर. के अनुसार 134 की तुलना में फिसलते हुए 136 पर आ पहुंचा है। भारत चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम सहित मध्यम मानव विकास श्रेणी में शामिल देश है। इन देशों की इसी श्रेणी में बेहतर समग्र एच.डी.आई रैंकिंग है। कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत में शिक्षा तथा स्वास्थ्य संकेतकों के मौजूदा अन्तराल को पाटने के लिए, शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य का प्रसार और तेजी एवं गहनता के साथ करना होगा। भारत में जीवन प्रत्याशा 2012 में 65.8 वर्ष थी, जबकि श्रीलंका में यह 75.1 वर्ष तथा चीन में 73.7 वर्ष है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर किया गया व्यय 2008-09 में 6.8 प्रतिशत था जोकि बढ़कर 2013-14 में 7.2 प्रतिशत हो गया है (बजट अनुमान) जिसमें शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया तथा इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया जाने वाला खर्च भी 1.3 प्रतिशत से बढ़कर 1.4 प्रतिशत हो गया है।

1.94 निर्धनता अनुपात 2004-05 में 37.2 प्रतिशत था जोकि घटकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रह गया है। समग्र संदर्भ में देखें तो निर्धनों की जो संख्या 2004-05 में 407.1 मिलियन थी, वह घटकर 2011-12 में 269.3 मिलियन रह गई है। 2004-05 से 2011-12 की अवधि में, रोजगार विकास (सीएजीआर) केवल 0.5 प्रतिशत था, जबकि 1999-2000 से 2004-05 की अवधि में यह 2.8 प्रतिशत रहा था। तथापि, सामान्य अवस्थानुसार (मूल + अनुषंगी) बेरोजगारी दर लगभग 2 प्रतिशत पर मंडराती रही है।

यदि समय रहते कार्रवाई न की गई तो मानव-आबादी का लाभ हमेशा उठाने की संभावना नहीं रहेगी।

सतत विकास और जलवायु परिवर्तन

1.95 सतत विकास सार्वभौमिक साम्यता हासिल करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। विकास की तदर्थवादी कारोबारी सामान्य दृष्टि के कारण अवहनीय उपभोग का पैटर्न सामने आया है जो कि मूलतः विकसित देशों की वजह से ही है। मानव-कृत्य ही जलवायु में परिवर्तन की असल वजह हैं। ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का उत्सर्जन स्तर 2000 और 2010 के बीच औसत 2.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर बढ़ा है जबकि 1970 और 2000 के बीच यह 1.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष हुआ करता था। 2010 में भारत में प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन का स्तर 1.7 मीट्रिक टन रहा, जोकि विश्व के प्रतिव्यक्ति औसत 4.9 मीट्रिक टन से अभी भी काफी कम है।

1.96 इस समय, सरकारें जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के बारे में दो नए करारों पर काम कर रही हैं। ये दोनों ही करार नए ग्लोबल दिशा-निर्देश होंगे जिन पर आधारित कार्रवाइयों को अगले वर्ष अमली जामा पहनाया जाएगा। रियो + 20 मैन्डेट के अनुसरण में ग्लोबल समुदाय एक वहनीय विकास परक उद्देश्यों (एसडीजी) की स्थापना करने के कार्य में लगा है। संभावित है कि 2015 के अंत तक इन्हें सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) में मिला दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में काम जारी है और एसडीजी से सम्बन्धित कई विषयपरक केन्द्रक क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है।

1.97 इस ग्लोबल समझौते में अत्यंत महत्वपूर्ण और अहम बात यह है कि इस नई संरचना में विकसित और विकासशील देशों की क्या हैसियत होगी। किसी भी भावी करार में भारत की चिन्ताओं और इसके विकासपरक सरोकारों का सम्यक ध्यान रखा जाना चाहिए। जरूरत यह सुनिश्चित किए जाने की है कि इस नए समझौते में समता साम्यता और साझे किन्तु विभेदीकृत दायित्वों को सुदृढ़तापूर्वक शामिल किया जाए। ग्लोबल वायुमंडलीय संसाधनों तक सभी की “समान” पहुंच और विकसित देशों का ऐतिहासिक दायित्व इन अंतर्राष्ट्रीय करारों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं का निर्धारक होना चाहिए। इसमें यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाए कि विकासशील देशों को अपेक्षित ‘कार्बन गुंजाइश’ और ‘विकास परक गुंजाइश’ पर्याप्त रूप में दी जाए। इसके क्रियान्वयन के तौर-तरीकों का मामला भी अहम है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी और ग्रीन क्लाइमेट फंड के गैर-पूंजीगत होने से ग्लोबल विचारविमर्श की साख को जोखिम हो सकता है।

1.98 भारत में बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सतत सम्मोषणीयता पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत ने 1990 और 2011 के दौरान जीडीपी के प्रतियूनिट कार्बन उत्सर्जन में 20 प्रतिशत की कमी की है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर जनवरी, 2012 में 23 गीगावाट तक जा पहुंची है, जोकि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता के 12 प्रतिशत के करीब है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) के कार्यान्वयन में अच्छी-खासी प्रगति हुई है। नौ राज्यों के एसएपीसीसी को समर्थन दिया जा चुका है।

1.99 भारत की निम्न कार्बन रणनीति की संचयी लागत का अनुमान एक विशेषज्ञ समूह द्वारा 2011 के मूल्यों के आधार पर 2010 और 2030 के बीच 834 बिलियन अमरीकी डॉलर किया गया है। चूंकि इस कार्य के लिए अपेक्षित संसाधन की मात्रा बहुत बड़ी है, अतः इसके चलते भारत के प्रयासों में अड़चन आ सकती है। ग्लोबल विमर्श धरती के संसाधनों के उचित तथा निष्पक्ष बंटवारे, अमीर तथा गरीब राष्ट्रों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने, अनुपयोगी उपभोग को समाप्त करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने, संसाधनों के उपयोग में लगातार दक्षता लाने के अवसर मुहैया कराता है। इस सब के मूल में निहित है—वैश्विक अधिकारों और दायित्वों-दोनों का ही न्यायसंगत बंटवारा।

2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या और अनुपात में उल्लेखनीय कमी देखी गई थी।

2010 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.7 मीट्रिक टन था, जो 4.9 मीट्रिक टन की वैश्विक औसत से काफी कम था।

नए जलवायु करारों में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि विकासशील देशों को अपेक्षित ‘कार्बन गुंजाइश’ और ‘विकास गुंजाइश’ प्रदान की गई है।
